



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक  
WEEKLY

सं. 50] नई दिल्ली, दिसम्बर 9—दिसम्बर 15, 2007, शनिवार/अग्रहायण 18—अग्रहायण 24, 1929

No. 50] NEW DELHI, DECEMBER 9—DECEMBER 15, 2007, SATURDAY/AGRAHAYANA 18—AGRAHAYANA 24, 1929

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक् संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधित आदेश और अधिसूचनाएं  
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India  
(Other than the Ministry of Defence)

कार्यिक, स्लोक शिक्षायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्यिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 5 दिसम्बर, 2007

का.आ. 3471.—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए असम राज्य सरकार के राजनीतिक (ए) विभाग की अधिसूचना सं. पीएलए. 159/2007/18—ए दिनांक 30 जून, 2007 द्वारा प्राप्त सहमति से राजस्व आसूचना निदेशालय, गुवाहाटी, असम के तरुण कुमार दत्ता, आसूचना अधिकारी की हत्या से संबंधित चांदमारी पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 302 संपादित आयुद्य अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 54) की धारा 27 और भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धारा 120-बी के

अधीन दर्ज मामला सं. 346/06 में अन्वेषण के लिए तथा उपर्युक्त उपराधों से संबंधित अथवा संस्कृत प्रयत्नों, दुष्प्रेरणों और घटयंत्रों तथा उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए तथा उन्हीं तथ्यों से उद्भूत किन्हीं अन्य अपराध/अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण असम राज्य पर करती है।

[फा. सं. 228/41/2007-एवीडी-II]

मनोजा सक्सेना, उप सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL,  
PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS  
(Department of Personnel and Training)

New Delhi, the 5th December, 2007

S.O. 3471.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the

Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of State Government of Assam Political (A) Department, Dispur vide Notification No. PLA 159/2007/18-A dated 30th June, 2007, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of State of Assam for investigation of Case No. 346/06 under Section 302 of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) read with Section 27 of the Arms Act, 1959 (Act No. 54 of 1959) Add. Section 120-B of the Indian Penal Code, 1860 (Act No. 45 of 1860) registered at Chandmari Police Station relating to murder of Tarun Kr. Dutta, Intelligence Officer of the Directorate Revenue Intelligence (DRI) Guwahati, Assam and any other offence/Offences, Attempts, abetments and conspiracy in relation to or in connection with above mentioned offences committed in the course of the same transaction arising out of the same facts.

[F. No. 228/41/2007-AVD-II]

MANISHA SAXENA, Dy. Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

**का.आ. 3472.**—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ परित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केरल राज्य सरकार, गृह (एम) विभाग की दिनांक 18 अगस्त, 2007 की अधिसूचना सं 71814/एम-3/2007/गृह द्वारा प्राप्त सहमति से मुहम्मद अल्ताफ की मृत्यु के संबंध में कोजीकोड जिले में पश्चोत्ती पुलिस स्टेशन के अपराध सं. 355/2005 में शामिल अपराधों के अन्वेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण केरल राज्य पर करती है, यह मामला पश्चोत्ती पुलिस स्टेशन के अपराध सं. 1/05 और अपराध सं. 158/05 से संबंधित मामलों से अंतर-संबंधित है जिन्हें पहले ही अन्वेषण के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को हस्तांतरित किया जा चुका है।

[फा. सं. 228/60/2005-ए वी डी. II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

**S.O. 3472.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 5 read with Section 6 of the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (Act No. 25 of 1946), the Central Government with the consent of State Government of Kerala Home (M) Department, vide

Notification No. 71814/M3/2007/Home dated 18th August, 2007, hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the Delhi Special Police Establishment to the whole of the State of Kerala for investigation of offences involved in Crime No. 355/2005 of Payyoli Police Station in Kozhikode District in connection with the death of Muhammed Althaf, the case inter connected with issues relating to Crime No. 1/05 and Crime No. 158/2005 of Payyoli Police Station which have already been transferred to Central Bureau of Investigation for investigation.

[No. 228/60/2005-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

**का.आ. 3473.**—केन्द्रीय सरकार एतद्वारा दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम सं. 2) की धारा 24 की उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए के.आ. ब्यूरो के अभियोजन अधिकारी श्री मोहम्मद फरीद को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना द्वारा किसी भी राज्य या संघ शासित क्षेत्र, में जिसमें उपरोक्त धारा लागू हो, विधि द्वारा स्थापित विचारण न्यायालय और अपील/पुनरीक्षण न्यायालय में मामलों या इनसे संबंधित मामलों का पुनरीक्षण या अपील न्यायालयों में संचालन करने के लिए विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 225/56/2007-एबीडी-II]

चंद्र प्रकाश, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

**S.O. 3473.**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (8) of Section 24 of Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Modh. Fareed, Prosecuting Officer of the Central Bureau of Investigation as Special Public Prosecutor for conducting cases instituted by the Delhi Special Police Establishment (CBI) in trials courts and appeals/revisions or other matters arising out of these cases in revisional or appellate Courts, established by law in any State or Union Territory to which provisions of the aforesaid Section apply.

[No. 225/56/2007-AVD-II]

CHANDRA PRAKASH, Under Secy.

## वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएँ विभाग)

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का.आ. 3474.—राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध एवं प्रकीर्ण उपबंध) स्कीम, 1970/1980 के खंड 3 के उपखंड (1) के साथ पठित बैंक कारो कैप्नी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 9 की उप-धारा 3(ज) और (3-क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री सतीय गोयल को अधिसूचना की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए अथवा उनके उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, कारोफारेशन बैंक के निदेशक मंडल में अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करती है।

[फा. सं. 9/22/2006-बीओ-I]

जी.बी. सिंह, उप सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

## (Department of Financial Services)

New Delhi, the 7th December, 2007

S.O. 3474.—In exercise of the powers conferred by sub-section 3(h) and (3-A) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 read with sub-clause (1) of clause 3 of the Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/1980, the Central Government hereby nominates Shri Satish Goel as part-time non-official director on the Board of Directors of Corporation Bank for a period of three years from the date of notification or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 9/22/2006-BO-I]

G.B. SINGH, Dy. Secy.

## वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का.आ. 3475.—केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 (1948 का 61) की धारा 4 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अध्यधीन इस अधिसूचना की तिथि से तीन वर्षों की अवधि के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए निम्नलिखित

व्यक्ति का नामांकन अधिसूचित करती है।

श्री अनिल कुमार, एम एल, उपर्युक्त अधिनियम की धारा सुपुत्र श्री वी लक्ष्मी गौड़ा, 4(3)(जे) के अंतर्गत केंद्र गांव मदनाहल्ली, पोस्ट : वेलागलबरी सरकार द्वारा नामित तालुक व जिला : कोलार (कर्नाटक)

[फा. सं. 25012/56/99-रेशम]

भूपेन्द्र सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 7th December, 2007

S.O. 3475.—In exercise of the powers conferred by Sub-section (3) of Section 4 of the Central Silk Board Act, 1948, the Central Government hereby notifies the nomination of the following person to serve as member of the Central Silk Board for a period of three years from the date of this notification subject to the provisions of the said Act.

Shri Anil Kumar, M.L., Nominated by the Central  
S/o Shri V. Lakshme Gowda, Government under Section  
Vill. Madanahally, 4(3)(J) of the Act.  
P.O. Velagalburre,  
Taluk & Distt. : Kolar  
(Karnataka)

[F.No. 25012/56/99-Silk]

BHUPENDRA SINGH, Jt. Secy.

## संचार और सूचना प्रौद्योगिक मंत्रालय

(डाक विभाग)

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2007

का.आ. 3476.—राजभाषा नियम (संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग) 1976 के नियम-10 के उप नियम (4) के अनुसरण में केन्द्र सरकार, डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को जिसके 80 प्रतिशत कर्मचारी (युप घ एवं कर्मचारियों को छोड़कर) ने हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है।

क्रम सं कार्यालयों का नाम	पिन कोड
1. चम्बा मंडलीय कार्यालय	176310
2. चम्बा मुख्य डाकघर	176310
3. बकलोह उप डाकघर	176301
4. बनीखेत उप डाकघर	176303

1	2	3
5.	बाथरी बाजार उप डाकघर	176306
6.	भरमौर उप डाकघर	176315
7.	भंजराडू तीसा उप डाकघर	176316
8.	भलेई उप डाकघर	176308
9.	चुकाड़ी उप डाकघर	176302
10.	डलहौजी उप डाकघर	176304
11.	डलहौजी कोर्ट रोड	176304
12.	डलहौजी कैट उप डाकघर	176305
13.	गैहरा उप डाकघर	176324
14.	गरोला उप डाकघर	176309
15.	हरदासपुरा उप डाकघर	176318
16.	ककीरा उप डाकघर	176313
17.	किलाड़ी पांगी उप डाकघर	176323
18.	खैरी उप डाकघर	176325
19.	मैहला उप डाकघर	176311
20.	नकरोड़ उप डाकघर	176321
21.	पुखरी उप डाकघर	176319
22.	रंग मेहल एन डी एस ओ	176310
23.	सिहुंता उप डाकघर	176207
24.	सुराणानी उप डाकघर	176317
25.	सुंडला उप डाकघर	176312
26.	सुलतानपुर उप डाकघर	176314
27.	सलूनी उप डाकघर	176320

[सं. 11017-1/2007-रा.भा.]

स. चक्रवर्ती, उप महानिदेशक  
(स्थापना एवं राजभाषा)MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND IT  
(Department of Posts)

New Delhi, the 3rd December, 2007

S.O. 3476.—In pursuance of Rule 10(4) of the  
Official Languages (Use for Official Purposes of the Union)

Rules 1976, the Central Government hereby notifies the following Subordinate Offices of the Department of Posts where 80 percent staff has acquired the working knowledge of Hindi :—

Sl.No.	Name of Office	Pin Code
1.	2	3
1.	Chamba Division	176310
2.	Chamba H.O.	176310
3.	Bakloh S.O.	176301
4.	Banikhet S.O.	176303
5.	Bathri-Bazar S.O.	176306
6.	Bharmour S.O.	176315
7.	Bhanjrau-Tissa S.O.	176316
8.	Bhalei S.O.	176308
9.	Chowari S.O.	176302
10.	Dalhousie	176304
11.	Dalhousie Court Road NDSO	176304
12.	Dalhousie Cantt. S. O.	176305
13.	Gehra S.O.	176324
14.	Garola S.O.	176309
15.	Hardaspure S.O.	176318
16.	Kakira S.O.	176313
17.	Killar-Pangi S.O.	176323
18.	Khairi S.O.	176325
19.	Mehla S.O.	176311
20.	Nakror S.O.	176321
21.	Pukhri S.O.	176319
22.	Rang Mehal NDSO	176310
23.	Sihunta S.O.	176207
24.	Surangani S.O.	176317
25.	Sundla S.O.	176312
26.	Sultanpur S.O.	176314
27.	Salooni	176320

[No. 11017-1/2007-OL]

S.K. CHAKRABARTI, Dy. Director General  
(Estt. & OL)

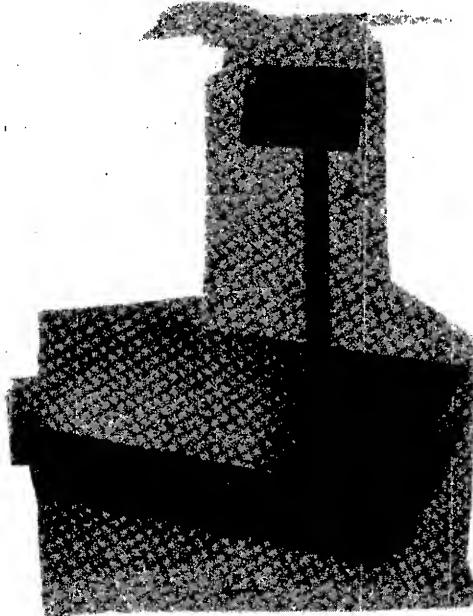
## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 2007

का.आ. 3477.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैटलर टोलेडो इंडिया प्राइवेट लिं., अमर हिल्स, साको विहार रोड, योवई, मुंबई-400072 द्वारा विनिर्मित विशेष यथार्थता (यथार्थता वर्ग-1) वाले “के” शृंखला के अंकक सूचन सहित अस्वचालित तोलन उपकरण के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “मैटलर टोलेडो” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/07/298 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी और प्रकाशित करती है;



उक्त मॉडल एक इलैक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स कम्पनसेशन सिद्धांत पर आधारित अस्वचालित तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 60 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 1 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यक्तलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। लिंविड क्रिस्टल डायोड (एल सी डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टार्मिंग प्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा और मॉडल को बिक्री से पहले या बाद में उसकी सामग्री, यथार्थता, डिजाइन, सर्किट डायग्राम निष्पादन सिद्धांत आदि की शर्तों पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो । मि. ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 50,000 से अधिक या उसके बराबर की रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 60 कि.ग्रा. की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान  $1 \times 10^8$ ,  $2 \times 10^8$  या  $5 \times 10^8$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(153)/2007]  
आर. माधुरबूथम, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

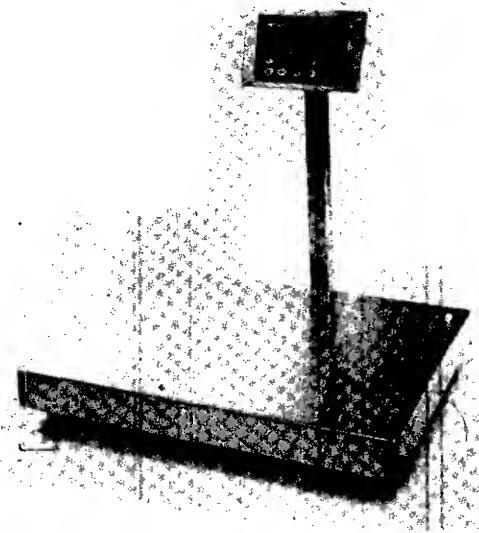
## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

New Delhi, the 15th November, 2007

**S.O. 3477.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of the Model of non-automatic weighing instrument with digital indication of "K" series of special accuracy (accuracy class-I) with brand name "METTLER TOLEDO" (herein referred to as the said Model), manufactured by M/s. Mettler-Toledo India Private Limited, Amar Hills, Saki Vihar Road, Powai, Mumbai-400 072 and which is assigned the approval mark IND/9/07/298;



The said Model is an Electro Magnetic Force Compensation Principle based non-automatic weighing instrument with a maximum capacity of 60kg and minimum capacity of 100g. the verification scale interval (e) is 1g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The Liquid Crystal Diode (LCD) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V., 50Hz alternative current power supply.

In addition to sealing the stamping plate sealing shall also be done to prevent opening of the machine for fraudulent practices and model shall not be changed in terms of its material, accuracy, design, circuit diagram, working principle etc. before or after sale.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instrument of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 60kg and with number of verification scale interval (n) equal to or more than 50,000 for 'e' value of 1mg or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , k being positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved model has been manufactured.

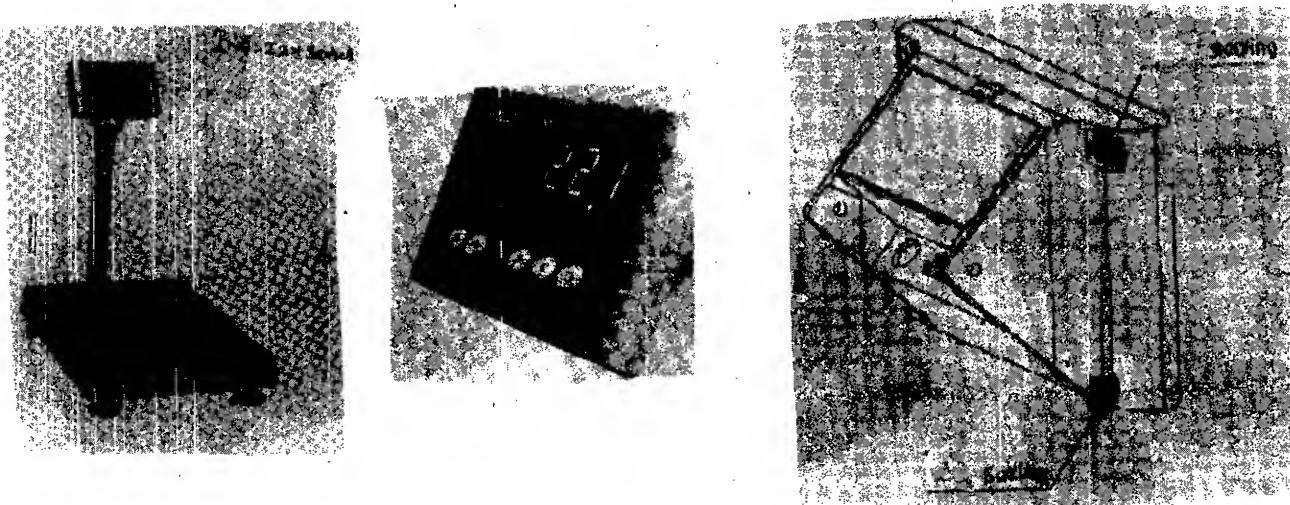
[F. No. WM-21(153)/2007]

R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

**का.आ. 3478.**—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और उप-धारा (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैटलर टोलडो इंडिया प्राइवेट लि., अमर हिल्स, एस वी, रोड, पोवाई, मुंबई-400072 महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-III) वाले “इंड 22×-टी” शृंखला के अस्वचालित अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (टेबल टॉप प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम “मैटलर टोलडो” है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/07/383 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है;



उक्त मॉडल एक विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (टेबल टॉप प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 30 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 100 ग्रा. है। सत्यापन मापमान अंतराल (ई) 5 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड, (एल ई डी) तोलन परिणाम उपर्युक्त करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ड्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।

स्टाम्पिंग स्लेट के मुद्रांकन के अतिरिक्त मशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोलने से रोकने के लिए सीलबंद भी किया जाएगा और मॉडल को बिन्दी से पहले या बाद में उसकी सामग्री, यथार्थता, डिजाइन, सर्किट डायग्राम निष्पादन सिद्धांत आदि की शर्तों पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। माडल के सीलिंग प्रावधान का विशिष्ट स्कीम डायग्राम ऊपर दिया गया है।

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही मेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 100 मि. ग्रा. से 2 ग्रा. तक के “ई” मान के लिए 100 से 10000 तक के रेज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 5 ग्रा. या उससे अधिक के “ई” मान के लिए 500 से 10000 तक की रेज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि. ग्रा. तक की अधिकतम क्षमता वाले हैं और “ई” मान  $1 \times 10^8$ ,  $2 \times 10^8$  या  $5 \times 10^8$ , के हैं, जो धनात्मक या ऋणात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

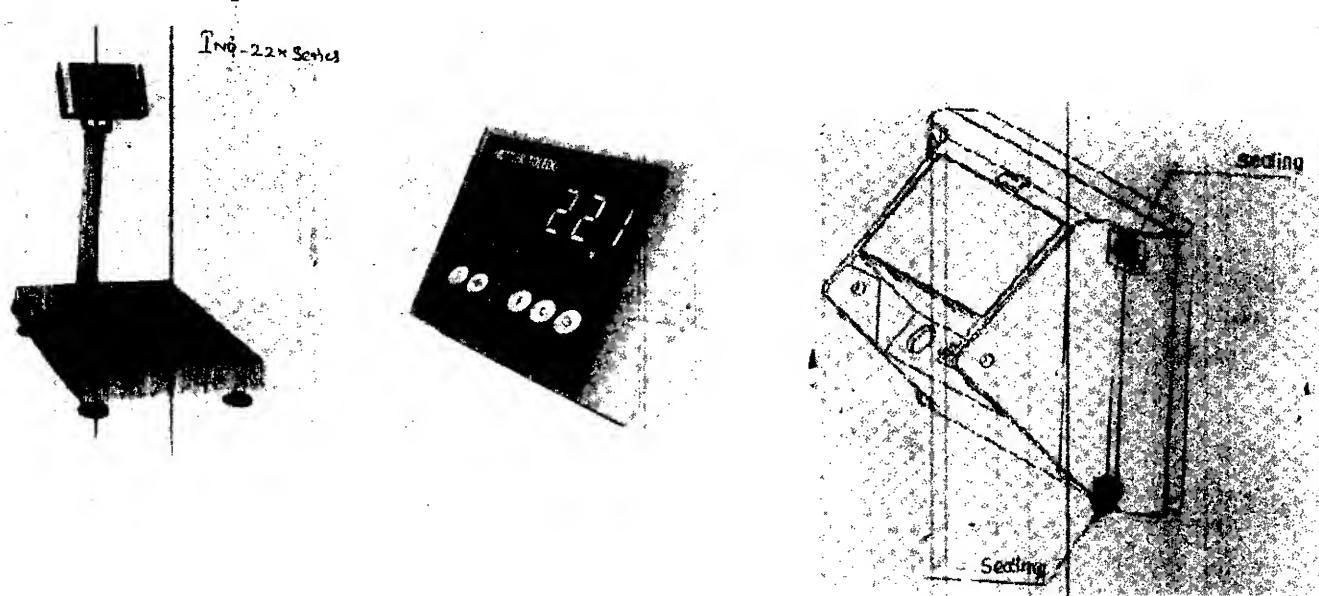
[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(189)/2007]  
आर. माधुरबूथम, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 16th November, 2007

S.O. 3478.—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic weighing instrument (Table top type) with digital indication of "IND 22x-T" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "Mettler-Toledo" (herein referred to as the said model), manufactured by M/s. Mettler-Toledo India Private Ltd., Amar Hills, S.V. Road, Powai, Mumbai-400 072, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/07/383;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Table top type) with a maximum capacity of 30kg and minimum capacity of 100g. The verification scale interval ( $e$ ) is 5g. It has a tare device with 100 per cent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V., 50Hz alternative current power supply.



In addition to sealing the stamping plate sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices and Model shall not be changed in terms of its material, accuracy, design, circuit diagram, working principle etc. A typical schematic diagram of sealing provision of the Model is given above.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity up to 50kg. with verification scale interval ( $n$ ) in the range of 100 to 10,000 for ' $e$ ' value of 100mg. to 2g. and with verification scale interval ( $n$ ) in the range of 500 to 10,000 for ' $e$ ' value of 5 g. or more and with ' $e$ ' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where  $k$  is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(189)/2007]

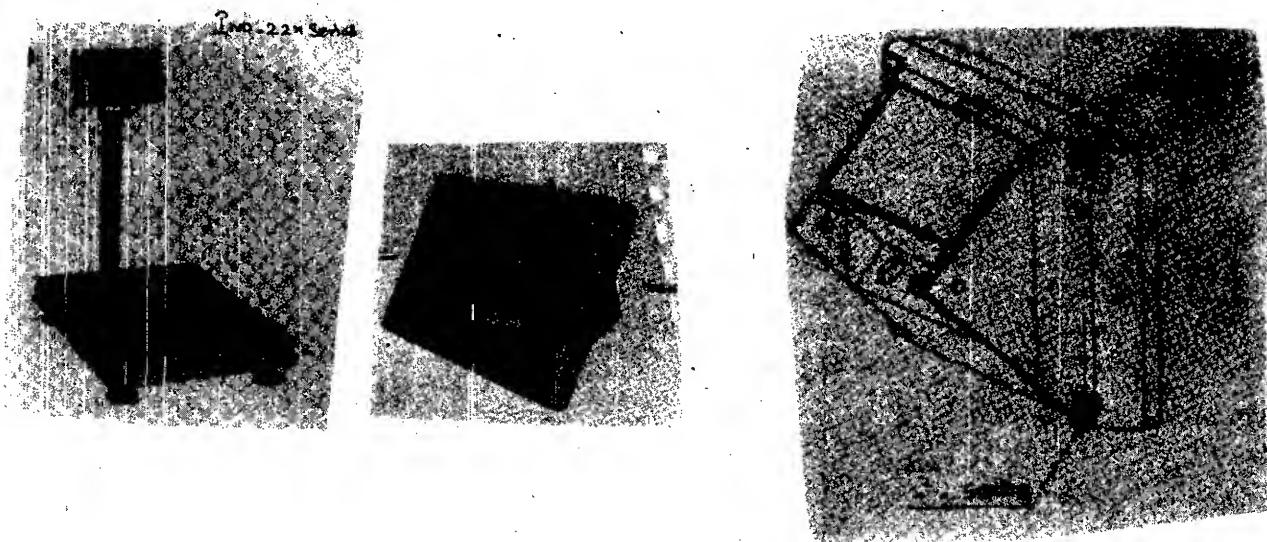
R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2007

का.आ. 3479.—केन्द्रीय सरकार का, विहित प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित मॉडल (नीचे दी गई आकृति देखें) बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 (1976 का 60) तथा बाट और माप मानक (मॉडलों का अनुमोदन) नियम, 1987 के उपबंधों के अनुरूप हैं और इस बात की संभावना है कि लगातार प्रयोग की अवधि में भी उक्त मॉडल यथार्थता बनाए रखेगा और विभिन्न परिस्थितियों में उपयुक्त सेवा प्रदान करता रहेगा;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (7) और (8) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैसर्स मैटलर टोलेडो इंडिया प्राइवेट लिं., अमर हिल्स, एस. बी. रोड, पोर्की, मुंबई-400 072 महाराष्ट्र द्वारा विनिर्मित मध्यम यथार्थता (यथार्थता वर्ग-I-III) वाले "इंड 22x-पी" शृंखला के अस्वचालित, अंकक सूचन सहित तोलन उपकरण (प्लेटफार्म प्रकार) के मॉडल का, जिसके ब्रांड का नाम "मैटलर टोलेडो" है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त मॉडल कहा गया है) और जिसे अनुमोदन चिह्न आई एन डी/09/07/384 समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र जारी करती है;

उक्त मॉडल विकृत गेज प्रकार का भार सेल आधारित अस्वचालित (प्लेटफार्म प्रकार) तोलन उपकरण है। इसकी अधिकतम क्षमता 1000 कि. ग्रा. है और न्यूनतम क्षमता 4 कि.ग्रा. है। सुन्यापन मापमान अंतराल (ई) 200 ग्रा. है। इसमें एक आधेयतुलन युक्ति है जिसका शत प्रतिशत व्यवकलनात्मक धारित आधेयतुलन प्रभाव है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एल ई डी) प्रदर्श तोलन परिणाम उपदर्शित करता है। उपकरण 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज प्रत्यावर्ती धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है।



स्थापित प्लेट को सील करने के अतिरिक्त भशीन को कपटपूर्ण व्यवहारों के लिए खोले जाने से रोकने के लिए भी सीलबंद किया जाएगा और मॉडल को बिक्री से पहले या बाद में उसकी सामग्री, यथार्थता, डिजाइन, सर्किट डायग्राम, निष्पादन सिद्धांत आदि की शर्तों पर परिवर्तित नहीं किया जाएगा। माडल के सीलिंग प्रावधान का विशिष्ट स्कीम डायग्राम ऊपर दिया गया है।

और, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 36 की उप-धारा (12) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त मॉडल के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत, डिजाइन के अनुसार और उसी सामग्री से, जिससे उक्त अनुमोदित मॉडल का विनिर्माण किया गया है, विनिर्मित उसी शृंखला के वैसे ही भेक, यथार्थता और कार्यपालन के तोलन उपकरण भी होंगे जो 5 ग्रा. या उससे अधिक के "ई" मान के लिए 500 से 10,000 तक के रेंज में सत्यापन मापमान अंतराल (एन) सहित 50 कि. ग्रा. से 5000 कि.ग्रा. तक की क्षमता वाले हैं और "ई" मान  $1 \times 10^4$ ,  $2 \times 10^4$  या  $5 \times 10^4$ , के हैं, जहाँ पर 'के' धनात्मक पूर्णांक या शून्य के समतुल्य हैं।

[फा. सं. डब्ल्यू एम-21(189)/2007]

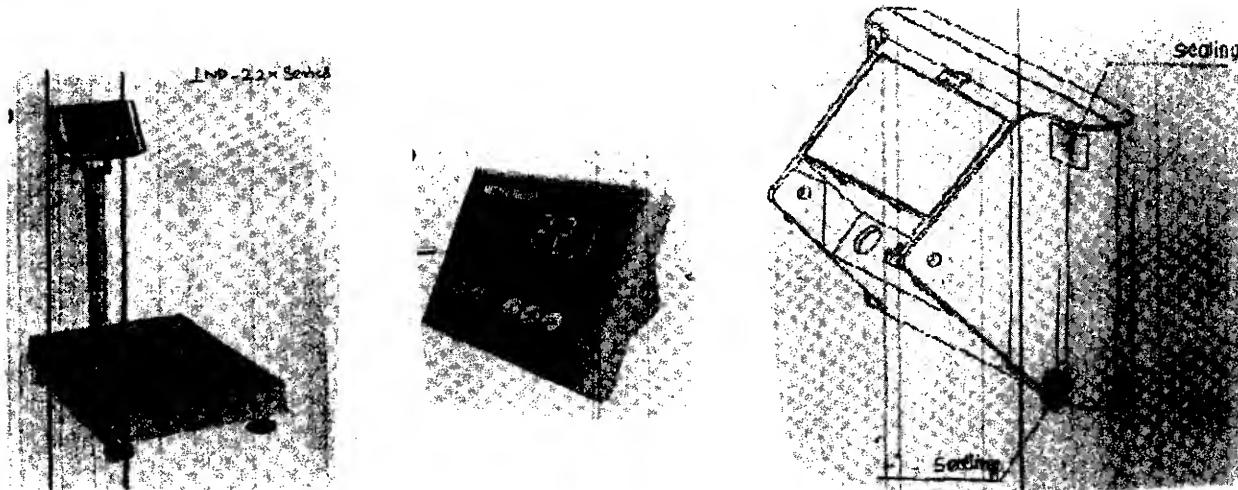
आर. माथुरबूधम, निदेशक, विधिक माप विज्ञान

New Delhi, the 16th November, 2007

**S.O. 3479.**—Whereas the Central Government, after considering the report submitted to it by the prescribed authority, is satisfied that the Model described in the said report (see the figure given below) is in conformity with the provisions of the Standards of Weights and Measures Act, 1976 (60 of 1976) and the Standards of Weights and Measures (Approval of Models) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain its accuracy over periods of sustained use and to render accurate service under varied conditions;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (7) and (8) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby issues and publishes the certificate of approval of non-automatic weighing instrument (Platform type) with digital indication of "IND 22xP" series of medium accuracy (accuracy class-III) and with brand name "Mettler Toledo" (hereinafter referred to as the said model), manufactured by M/s. Mettler-Toledo India Private Ltd., Amar Hills, S.V. Road, Powai, Mumbai-400 072, Maharashtra and which is assigned the approval mark IND/09/07/384;

The said model is a strain gauge type load cell based non-automatic weighing instrument (Platform type) with a maximum capacity of 1000kg and minimum capacity of 4kg. The verification scale interval (e) is 200g. It has a tare device with 100 percent subtractive retained tare effect. The light emitting diode (LED) display indicates the weighing result. The instrument operates on 230V., 50Hz alternative current power supply.



In addition to sealing the stamping plate sealing shall also be done to prevent the opening of the machine for fraudulent practices and Model shall not be changed in terms of its material, accuracy, design, circuit diagram, working principle etc. A typical schematic diagram of sealing provision of the Model is given above.

Further, in exercise of the powers conferred by sub-section (12) of Section 36 of the said Act, the Central Government hereby declares that this certificate of approval of the said model shall also cover the weighing instruments of similar make, accuracy and performance of same series with maximum capacity above 50kg. and upto 5000 kg. with verification scale interval (n) in the range of 500 to 10,000 for 'e' value of 5g. or more and with 'e' value of  $1 \times 10^k$ ,  $2 \times 10^k$  or  $5 \times 10^k$ , where k is a positive or negative whole number or equal to zero, manufactured by the same manufacturer in accordance with the same principle, design and with the same materials with which, the said approved Model has been manufactured.

[F. No. WM-21(189)/2007]  
R. MATHURBOOTHAM, Director of Legal Metrology

भारतीय मानक व्यूरो  
नई दिल्ली, 29 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3480.—भारतीय मानक व्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक व्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक (कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :-**

**अनुसूची**

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधित लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आई एस 1248 (भाग 1) 2003 प्रत्यक्ष क्रियाशील सूचक अनुरूप वैद्युत मापन उपकरण तथा उनके सहायक उपकरण भाग 1 परिभाषा तथा सामान्य अपेक्षाएँ (चौथा पुनरीक्षण)	1 अक्टूबर, 2007	31 नवम्बर, 2007

इस भारतीय संशोधन की प्रतियाँ भारतीय मानक व्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूणे तथा तिरुवनंतपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : ईटी 12/टी-1]

पी. के. मुखर्जी, वैज्ञानिक एवं प्रमुख (विद्युत तकनीकी)

**BUREAU OF INDIAN STANDARDS**

New Delhi, the 29th November, 2007

**S.O. 3480.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rules (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the amendment to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed has been issued :**

**SCHEDULE**

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards	No & year of the Amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 1248 (Part 1) : 2003 Direct acting indicating Analogue Electrical measuring Instruments and their accessories Part 1 Definitions and general requirements (Fourth Revision)	1 October, 2007	31 November, 2007

Copy of this Amendment is available with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, and Thiruvananthapuram.

[Ref: ET 12/T-1]

P. K. MUKHERJEE, Sc. F & Head (Electrotechnical))

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3481.—भारतीय मानक व्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक व्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन मानकों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक (कों) की संख्या वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हों, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 8692(भाग 3):2007/आईएसओ 3338-3:1996 मिलिंग कटर के लिए बेलनाकार शैंक भाग 3 चूड़ीदार शैंक के आयामी अभिलक्षण	—	सितम्बर, 2007
2.	आईएस 8919:2007/आईएसओ 2905:1985 मशीन औजार निर्माण के लिए माँडुयूलर इकाईयां वह सिपंडल शीर्षों के लिए सिपंडल नोज और समायोजनीय एडाप्टर (पहला पुनरीक्षण)	—	जनवरी, 2007
3.	आईएस 15371 (भाग 2):2007/आईएसओ/टीएस 14253-2:1999 ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ (जी.पी.एस.)—वर्कपीस के मापन द्वारा निरीक्षण तथा मापक उपस्कर भाग 2 मापन उपस्कर के अंशशोधन में, उत्पाद सत्यापन में और जी. पी. एस. मापन में अनिश्चितता आकलन को मार्गदर्शिका	—	अगस्त, 2007
4.	आईएस 15371 (भाग 3):2007/आईएसओ/टीएस 14253-3:2002 ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ (जी.पी.एस.)—वर्कपीस के मापन द्वारा निरीक्षण तथा मापक उपस्कर भाग 3 मापन अनिश्चितता कथनों पर करार के मार्गदर्शी सिद्धांत	—	सितम्बर, 2007
5.	आईएस 15759:2007/आईएसओ 12179:2000 ज्यामितीय उत्पाद विशिष्टियाँ (जी.पी.एस.)सह की बनावट: प्रोफाइल पद्धति-संपर्क (स्टाइलस) उपकरणों का अंशशोधन	—	अगस्त, 2007
6.	आईएस 15762:2007/आईएसओ 5413:1993 मशीन औजार—मोर्स टेपर्स का पाँजीटिव ड्राइव	—	सितम्बर, 2007

इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक व्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूर्णे तथा तिरुवनन्तपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : पीजीडी/जी-3.5]

पी. सी. जोशी, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (पीजीडी)

New Delhi, the 6th December, 2007

S.O. 3481.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

## SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Establish- ment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 8692 (Part 3): 2007/ISO 3338-3:1996 Cylindrical shanks for milling cutters Part 3 Dimensional characteristics of threaded shanks	—	September, 2007
2.	IS 8919: 2007/ISO 2905:1985 Modular units for machine tool construction— Spindle noses and adjustable adaptors for multi spindle heads (first Revision)	—	January, 2007
3.	IS 15371 (Part 2): 2007/ISO Geometrical product specifications (GPS)—Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment Part 2 Guide to the estimation of un- certainty in GPS measurement, in calibration of measuring equipment and in product verification	—	August, 2007
4.	IS 1537 (Part 3):2007 Geometrical product specifications (GPS)— Inspection by measurement of workpieces and measuring equipment Part 3 Guidelines for achieving agreements on measure- ment uncertainty statements	—	September, 2007
5.	IS 15759: 2007/ISO 12179:2000 Geometrical product specifications (GPS)—Surface texture: Profile Method—Calibration of conduct (stylus) Instruments	—	August, 2007
6.	IS 15762:2007/ISO 5413:1993 Machine tools—Positive drive of morse tapers	—	September, 2007

Copy of these standard is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: PGD/G-3.5]

P. C. JOSHI, Scientist 'E' &amp; Head (PGD)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3482.—भारतीय मानक व्यूरो नियम, 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक व्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि निम्न भारतीय मानक में रंशोधन किया गया/किये गये हैं :—

## अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 14181 (भाग 1): 2002 संशिलष्ट (प्लास्टिक) सरकवां फास्टनर-विशेष प्रयोजन-भाग 1 उत्पाद के लिए विशिष्ट, चयन एवं भाग का रूप (पहला पुनरीक्षण)	1	मार्च, 2007

इस भारतीय मानक के संशोधनों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्लूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों: अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूर्णे तथा तिरुवनन्तपुरम में बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : पीजीडी/जी-3.5]

पी. सी. जोशी, वैज्ञानिक 'ई' एवं प्रमुख (पीजीडी)

New Delhi, the 6th December, 2007

S.O. 3482.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been amended on the date indicated against each :

## SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. of Amendments and Date	Date of Establishment
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 14181 (Pt I): 2002 Specification, selection and ordering guideline of the product (first revision)	1	March, 2007

Copy of these Amendments of Standards is available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: PGD/G-3.5]

P. C. JOSHI, Scientist 'E' Head (PGD)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3483.—भारतीय मानक ब्लूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्लूरो एवं इसका अधिसूचित करता है कि जिन भारतीय मानकों के विवरण न-ऐचे अनुसूची में दिए गए हैं वे स्थापित हो गए हैं :—

## अनुसूची

क्रम सं.	स्थापित भारतीय मानक(कों) की संख्या, वर्ष और शीर्षक	नये भारतीय मानक द्वारा अतिक्रमित भारतीय मानक अथवा मानकों, यदि कोई हो, की संख्या और वर्ष	स्थापित तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 15741:2007 वस्त्रादि-पर्दों और ढेरपों की अनिं अवरोधकता -विशिष्टि	—	जून, 2007

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	आई एस 15742:2007 वस्त्रादि- सीमित ज्वाला फैलाने की वस्तुओं से बनी उष्मा एवं ज्वाला से बचाव करने वाली वस्त्र सामग्री की अपेक्षाएँ- विशिष्टि	—	जून, 2007

इन भारतीय मानकों की प्रतियाँ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शांखा कार्यालयों; अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, पटना, पूर्णे तथा तिरुवनन्तपुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : टीएक्सडी/जी-25]

एम. एस. वर्मा, निदेशक एवं प्रमुख (टीएक्सडी)

New Delhi, the 6th December, 2007

S.O. 3483.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been established on the date indicated against each :

#### SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards Established	No. & year of Indian Standards, if any, Superseded by the New Indian Standard	Date of Established
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 15741:2007 Textiles—Resistance to Ignition of Curtains and Drapes—Specification	—	June, 2007
2.	IS 15742:2007 Textiles—Requirements for Clothing made of Limited Flame Spread Materials and Material Assemblies affording Protection against Heat and Flame— Specification	—	June, 2007

Copy of these Standards are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices : New Delhi, Kolkata, Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices : Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref : TXD/G-25]

M. S. VERMA, Director & Head (Textiles)

नई दिल्ली, 06 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3484.—भारतीय मानक ब्यूरो नियम 1987 के नियम 7 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एतद्वारा अधिसूचित करता है कि नीचे अनुसूची में दिए गए मानक(कों) में संशोधन किया गया/किये गये हैं :—

## अनुसूची

क्रम सं.	संशोधित भारतीय मानक की संख्या और वर्ष	संशोधन की संख्या और तिथि	संशोधन लागू होने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	आईएस 2422:1985	संशोधन संख्या 3 नवम्बर, 2007	नवम्बर, 2007

इस संशोधन की प्रति भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन, 9 बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110 002, क्षेत्रीय कार्यालयों : नई दिल्ली, कोलकाता, चण्डीगढ़, चेन्नई, मुम्बई तथा शाखा कार्यालयों : अहमदाबाद, बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, कोयम्बतूर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, नागपुर, पटना, पूर्णे तथा तिरुवनन्तापुरम में विक्री हेतु उपलब्ध हैं।

[संदर्भ : टी एक्स/जी-25]

एम. एस. वर्मा, निदेशक एवं प्रमुख (टीएक्सडी)

New Delhi, the 6th December, 2007

S.O. 3484.—In pursuance of clause (b) of sub-rule (1) of Rule 7 of the Bureau of Indian Standards Rules, 1987, the Bureau of Indian Standards hereby notifies that ammendents to the Indian Standards, particulars of which are given in the Schedule hereto annexed have been issued :

## SCHEDULE

Sl. No.	No. & Year of the Indian Standards	No. & year of the amendment	Date from which the amendment shall have effect
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	IS 2422:1985	Amendment No. 3 November, 2007	November, 2007

Copy of these Amendments are available for sale with the Bureau of Indian Standards, Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110 002 and Regional Offices: New Delhi, Kolkata Chandigarh, Chennai, Mumbai and also Branch Offices: Ahmedabad, Bangalore, Bhopal, Bhubaneshwar, Coimbatore, Guwahati, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Nagpur, Patna, Pune, Thiruvananthapuram.

[Ref: TXD/G-25]

M. S. VERMA, Director & Head (Textiles)

नई दिल्ली, 06 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3485.—भारतीय मानक ब्यूरो (प्रमाणन) विनियम 1988 के नियम (4) के ऊपर नियम (5) के अनुसरण में भारतीय मानक ब्यूरो एकद्वारा अधिसूचित करता है कि जिन लाइसेंसों के विवरण नीचे अनुसूची में दिए गए हैं, वे स्वीकृत (Granted) कर दिये गए हैं:-

## अनुसूची

क्रम सं.	लाइसेंस सं.	चालू तिथि	लाइसेंसधारी का नाम व पता	भारतीय मानक का शीर्षक व संबंधित भारतीय मानक
1	2	3	4	5
अक्टूबर 2007				
01	8864405	29-09-2007	मैसर्स एस.के.इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) 190 ए, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर- 302 012 (राजस्थान)	8794:1988 सीआईडी ज्वार्इन्ट्स

1	2	3	4	5
02	8865508	03-10-2007	मैसर्स वर्धमान ज्वैलर्स अग्रसेन मार्केट सांगरिया, हनुमानगढ़-335063 (राजस्थान)	1417:1999 स्वर्णाभूषणों की हालमार्किंग
03	8865609	03-10-2007	मैसर्स न्यू लाईट ज्वैलर्स 85, जवाहर मार्केट श्री गंगानगर-335001 (राजस्थान)	1417:1999 स्वर्णाभूषणों की हालमार्किंग
04	8866308	03-10-2007	मैसर्स सूरज बुड इण्डस्ट्रीज प्लॉट नं. डी-44 एवं डी-44 जी औद्योगिक क्षेत्र, कालाडेरा जयपुर (राजस्थान)	2202 (Part 1):1999 फ्लश डार शर्ट्स
05	8866813	05-10-2007	मैसर्स जयपुर सिल्वर हाउस जी-1-2, अरिहन्त टावर -II, सांगनेरी गेट, आगरा रोड जयपुर-302 003 (राजस्थान)	1417:1999 स्वर्णाभूषणों की हालमार्किंग
06	8866914	09-10-2007	मैसर्स जयपुर सिल्वर हाउस जी-1-2, अरिहन्त टावर -II, सांगनेरी गेट, आगरा रोड जयपुर-302 003 (राजस्थान)	2112 : 2003 रजत आभूषणों की हालमार्किंग.
07	8868413	04-10-2007	मैसर्स अनामिका कण्डकर्स लिमिटेड 4,5,6,10 एवं 11 मालवीय औद्योगिक क्षेत्र जयपुर-302017 (राजस्थान)	7098 (Part 1):1988 एक्सएलपीई इनसुलेटेड पीवीसी केबल्स
08	8870194	17-10-2007	मैसर्स दीवान ज्वैलर्स शॉप नं. 3 एवं 4, सनी आर्केड 1888, तेलीपाडा, चौड़ा रास्ता जयपुर - 302 003 (राजस्थान)	2112:2003 रजतआभूषणों की हालमार्किंग
09	8870093	16-10-2007	मैसर्स दीवान ज्वैलर्स शॉप नं. 3 एवं 4, सनी आर्केड 1888, तेलीपाडा, चौड़ा रास्ता जयपुर - 302 003 (राजस्थान)	1417:1999 स्वर्णाभूषणों की हालमार्किंग
10	8872606	24-10-2007	मैसर्स खण्डाका जैन ज्वैलर्स 3-4, हल्डियों का रास्ता जौहरी बाजार जयपुर-302 003 (राजस्थान)	1417:1999 स्वर्णाभूषणों की हालमार्किंग

1	2	3	4	5
11	8872303	23-10-2007	मैसर्स कोठारी पोलीमर्स प्लॉट नं. 13, औद्योगिक क्षेत्र-II मंगलवार चौराहा, चित्तौडगढ़ (राजस्थान)	14151 (Part 2):1999 क्यू सी पी ई पाईप्स
12	8869617	12-10-2007	मैसर्स लक्ष्मणवीर स्टील (प्रा.) लि. 65-ए, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर -302012 (राजस्थान)	1786:1985 एचएसडी स्टील बार्स एण्ड वायर्स
13	8872808	24-10-2007	मैसर्स माणिड्या पोलीमर्स प्रा.लि. एन.एच.नं. 11, नरोदरा लक्ष्मणगढ़, जिला-सीकर (राजस्थान)	14151 (Part 2):1999 क्यू सी पी ई पाईप्स
14	8868514	08-10-2007	मैसर्स नवभारत ट्यूब्स लिमिटेड 94-डी, औद्योगिक क्षेत्र झोटवाडा, जयपुर -302012 (राजस्थान)	4923:1997 हॉलो स्टील सैक्षान्स फॉर स्ट्रक्चरल यूज
15	8868312	11-10-2007	मैसर्स शुभांग ज्वैल्स 50, ग्राउण्ड फ्लोर गणपति प्लाजा एम.आई रोड, जयपुर- 302001 (राजस्थान)	1417:1999 स्वर्णाभूषणों की हालमार्किंग
16	8872202	23-10-2007	मैसर्स सादिया प्लास्टिक इण्डस्ट्रीज एफ-201-सी, माणिड्या रोड पॉवर हाउस के पास पाली मारवाड- 306401 जिला-पाली (राजस्थान)	14151 (Part 2):1999 क्यू सी पी ई पाईप्स
17	8869011	09-10-2007	मैसर्स वैंकटेशवर वायर्स प्रा.लि. सी-116 (ए-1), रोड नं. 8 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर-302013 (राजस्थान)	1554 (Part 1):1988 पीवीसी इन्सुलेटेड (एचडी) केबल्स
18	8869112	09-10-2007	मैसर्स वैंकटेशवर वायर्स प्रा.लि. सी-116 (ए-1), रोड नं. 8 विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र जयपुर-302013 (राजस्थान)	7098 (Part 1):1988 एक्सएलपीई इन्सुलेटेड पीवीसी केबल्स

[सं. सी एम डी/13:11]  
अशोक तलवार, उप महानिदेशक (मुहर)

New Delhi, the 6th December, 2007

S.O. 3485.—In pursuance of sub-regulation (5) of regulation 4 of the Bureau of Indian Standards (Certification Regulation, 1988, the Bureau of Indian Standards, hereby notifies the grant of licence particulars of which are given in the following schedules.

## SCHEDULE

Sl. No.	Licence No. (CM/L-)	Operative Date (3)	Name and Address of the Licensee (4)	Article/Process Covered by the licences and the relevant IS:Designation (5)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Oct 2007		
01.	8864405	29-09-2007	S.K. Industries (India) 190 A Industrial area Jhotwara, Jaipur-302012 Rajasthan	8749:1988 CID Joints
02.	8865508	03-10-2007	Vardhman Jewellers Ageraing Market Sangaria, Hanumangarh- 335063 Rajasthan	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
03.	8865609	03-10-2007	New Light Jewellers 85-Jawahar Market Sri Ganganagar-335001 Rajasthan	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
04.	8866308	03-10-2007	Suraj Wood Industries Plot No. D-44F & D-44G Industrial Area Kaladera, Jaipur Rajasthan	2202 (Part 1):1999 Flush Door Shutters
05.	8866813	05-10-2007	Jaipur Silver House G-1-2, Arihant Tower-II, Sanganari Gate, Agra Road Jaipur-302003 Rajasthan	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
06.	8866914	09-10-2007	Jaipur Silver House G-1-2, Arihant Tower-II, Sanganari Gate, Agra Road Jaipur-302003 Rajasthan	2112:2003 Hallmarking of Silver Jewellery
07.	8868413	04-10-2007	Anamika Conductors Limited 4,5,6,10&11 Malviya Industrial Area Jaipur-302017 Rajasthan	7098 (Part 1):1988 XLPE Insulated PVC Cables
08.	8870194	17-10-2007	Dewan Jewellers Shop No. 3 &4, Sunny Arcade 1888,Teli Para, Chaura Rasta Jaipur-302003 Rajasthan	2112:2003 Hallmarking of Silver Jewellery
09.	8870093	16-10-2007	Dewan Jewellers Shop No. 3 &4, Sunny Arcade 1888, Teli Para, Chaura Rasta Jaipur-302003 Rajasthan	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
10.	8872606	24-10-2007	Khandaka Jain Jewellers 3-4 Haldiyon Ka Rasta, Johari Bazar Jaipur-302003 Rajasthan	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
11.	8872303	23-10-2007	Kothari Polymers Plot No.13, Industrial Area-II Mangalwar Choraha Chittorgarh Rajasthan	14151 (Part 2):1999 QCPE Pipes
12.	8869617	12-10-2007	Lakshmanveer Steel (P) Ltd. 65-A, Industrial Area Jhotwara, Jaipur-302012 Rajasthan	1786:1985 HSD Steel Bars & Wires
13.	8872808	24-10-2007	Mandia Polymers Pvt. Ltd. N.H. No.11, Narodara Laxmangarh Sūkar Rajasthan	14151 (Part 2):1999 QCPE Pipes
14.	8868514	08-10-2007	Navbharat Tubes Limited 94-D, Industrial Area Jhotwara, Jaipur-302012 Rajasthan	4923:1997 Hollow Steel Sections for Structural use
15.	8868312	11-10-2007	Shubhang Jewels 50, Ground Floor, Ganpati Plaza M1 Road, Jaipur-302001 Rajasthan	1417:1999 Hallmarking of Gold Jewellery
16.	8872202	23-10-2007	Sadiya Plastic Industries F-201-C, Mandia Road Near Power House, Pali Marwar Pali-306401 Rajasthan	14151 (Part 2):1999 QCPE Pipes
17.	8869011	09-10-2007	Venkateshwara Wires Pvt. Ltd. C-116(A-1), Road No. 08 V.K.I. Area, Jaipur-302013 Rajasthan	1554 (Part 1):1988 PVC Insulated (HD) Cables
18.	8869112	09-10-2007	Venkateshwara Wires Pvt. Ltd. C-116(A-1), Road No. 08 V.K.I. Area, Jaipur-302013 Rajasthan	7098 (Part 1):1988 XLPE Insulated PVC Cables

[No. CMD/13:11]

A.K. TALWAR, Dy. Director General (Marks)

## पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3486.— तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 47) की उपधारा (3) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा श्री अरुण कुमार, सी एस एस (1975), को दिनांक 5-12-2007 से पांच साल की अवधि के लिए, या उनके सेवानिवृत्त होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, जो भी पहले हो, तेल उद्योग विकास बोर्ड का सचिव नियुक्त करती है।

[सं. जी-35012/3/07-वित्त- II]

एस.सी.दास, अवर सचिव

## MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

New Delhi, the 10th December, 2007

S.O. 3486.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (3) of Section 3 of the Oil Industry (Development) Act, 1974 (47 of 1974), the Central Government hereby appoints Shri Arun Kumar, CSS (1975) as Secretary, Oil Industry Development Board with effect from 5-12-2007 for a period of five years or till date of his superannuation or until further orders, whichever is earlier.

[No. G-35012/3/07-Fin.II]

S. C. DAS, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3487.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रत्तलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं. 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

तालुका : वडोदरा	जिला : वडोदरा		राज्य : गुजरात		
			उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल	
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.		हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
आसोज	242	-	0	03	40

[फा. सं. आर-25011/5/2006-ओ.आर.-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

S. O. 3487.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

**Schedule**

Tehsil:-Vadodara Name of Village	District:-Vadodara Survey No/Block No	Sub-Division No.	State :-Gujarat Area		
			Hectare	Are	Centiare
1 Asaj	2 242	3 -	4 0	5 03	6 40

[F. No. R-25011/5/2006-O.R.-I]  
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, ७ दिसम्बर, 2007

का. आ. 3488.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाउन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं. 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा — 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

तालुका : गोधरा	जिला : पंचमहल	उप खण्ड सं.	राज्य : गुजरात		
			क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
गोलाव	311	2	0	18	93
	310	P	0	07	20
	324	2	0	24	12
	266	1	0	10	08
	265	P8	0	05	33
	265	8	0	15	12
	265	P8	0	00	67
	265	1	0	08	28
	270	1	0	04	98
	448	P1	0	18	60
	449	1	0	08	64
	449	2B	0	10	75
	538	P	0	11	70
	522	P	0	07	35
	644	3	0	29	97
	644	1	0	06	90
	643	P3	0	17	46
	643	2	0	01	04
	642	P	0	20	06

1	2	3	4	5	6
ગોલાવ (ખારી...)	643	P2	0	08	82
	635		0	20	30
	632		0	47	48
	629	P2	0	15	12
	628		0	36	00
	665	1	0	11	70
દહીકોટ	223	Old173P	0	01	08
	229	Old172/3	0	29	10
	218	Old162	0	23	76
	211	Old156/3	0	07	92
	209	Old155	0	11	70
	70P	Old47P	0	05	22
	70P	47/1P	0	25	02

[ફા. સં. આર-25011/7/2006-ઓ.આર.-1]

એસ. કે. ચિટકારા, અવર સचિવ

New Delhi, the 7th December, 2007

S. O. 3488.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

## Schedule

Tehsil:-Godhara Name of Village	District:-Panchmahal		State :-Gujarat		
	Survey No/Block No	Sub-Division No.	Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Gollav	311	2	0	18	93
	310	P	0	07	20
	324	2	0	24	12
	266	1	0	10	08
	265	P8	0	05	33
	265	8	0	15	12
	265	P8	0	00	67
	265	1	0	08	28
	270	1	0	04	98
	448	P1	0	18	60
	449	1	0	08	64
	449	2B	0	10	75
	538	P	0	11	70
	522	P	0	07	35
	644	3	0	29	97
	644	1	0	06	90
	643	P3	0	17	46
	643	2	0	01	04
	642	P	0	20	06
	643	P2	0	08	82
	635	-	0	20	30
	632	-	0	47	48
	629	P2	0	15	12
	628	-	0	36	00
	665	1	0	11	70
Dahikot	233	Old173P	0	01	08
	229	Old172/3	0	29	10
	218	Old162	0	23	76
	211	Old156/3	0	07	92
	209	Old155	0	11	70
	70P	Old47P	0	05	22
	70P	47/1P	0	25	02

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]  
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3489.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रत्लाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए:

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं. 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

तालुका : कालोल	जिला : पंचमहल	उप खण्ड सं.	राज्य : गुजरात		
			क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एकर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
माधवास	111	1	0	03	13
	166	P	0	01	80
	170	1	0	07	06
	101	1P	0	07	47
	166	1P	0	02	81
	166	P2	0	08	10
	211	P2	0	14	76
211+191+193	P1+P2,P1,1P		0	28	30
	212	1+P2	0	01	30
	236	P1+P2	0	45	76
	269	P2	0	06	83
जेतपुर	313	P	0	04	32
	313	P	0	01	50
	308	P	0	15	12
	308	P	0	11	70
	308	P	0	04	68
	308	P1/1	0	08	64
	308	P	0	08	64
	294	P	0	06	12

1	2	3	4	5	6
जीतपुर निरन्तर***	109	P	0	15	97
	109	P	0	00	90
	109	P/1	0	11	52
	109	P	0	13	94
	109	P	0	01	89
	108	P	0	05	10
	108	P	0	03	00
	119	P	0	10	17
	125	P	0	13	05
	125	P	0	08	10
	294	2P	0	13	50
	129	P	0	14	40
	129	P	0	09	72
	129	P	0	03	60
	129	P	0	00	68
	129	P2	0	14	85
	153	2	0	18	00
	143	2	0	07	44
	147	2	0	12	24
	147	P1	0	05	04
	147	1P	0	05	72
कंडाच	451	1	0	07	77
	294	3	0	01	01
	295	1	0	05	94
	295	P2	0	05	76
	620	-	0	11	16
	621	2,1	0	10	44
	622	2P4	0	04	50
	622	1P,2	0	05	58
	623	7	0	07	56
	624	2	0	09	72
	625	-	0	14	58
	628	-	0	00	80
	623	P	0	12	96
उत्तरेडिया	44	1+2	0	02	88
	45	2+3	0	38	32
	94	5	0	10	80
	102	3	0	07	02
	146	1P	0	03	08
	136	1	0	03	42
व्यासडा	1194	-	0	11	70
	1458	-	0	00	95
भुखी	69	3	0	05	58
	86	P	0	01	42
	116	3	0	04	12
	113	3	0	08	10
	112	4	0	05	49
	125	-	0	03	78
	87	2	0	27	40

1	2	3	4	5	6
फन्सी	26	4	0	10	08
	41	3	0	16	02
	44	5	0	03	41
	44	3	0	15	01
	44	3	0	00	10
	6	2	0	04	68
	7	4	0	07	53
	44	2	0	01	10
	44	3	0	09	89
	44	4	0	01	81
	7	2	0	10	62
करोली	330	1PPlot20	0	08	96
	330	1P/21/2	0	12	14
	330	1P/21/3	0	11	79
	330	1P	0	00	24
	330	1-21/1/7	0	00	77
	330	1P	0	12	06
	330	1PPlot164	0	08	36
	330	1P	0	15	84
	330	1P	0	10	98
	330	1P	0	07	92
	330	1P	0	07	02
	330	1P	0	11	76
	330	1P	0	05	04
	330	1P	0	08	10
	308	1P1	0	22	86
	309	1	0	14	94
	313	2	0	19	88
	330	1P	0	22	60
	330	1P	0	19	44
	320	3	0	09	99
	321	2	0	10	19
	330	1P	0	63	72
	330	1Plot226	0	26	46
	330	1P	0	23	40
	330	plot12	0	00	44
	330	1P	0	29	88
	330	1P	0	00	54
	330	1	0	13	86
	330	1P	0	07	92
	256	2	0	17	64
	255	2/1P2	0	05	76
	330	22/1	0	12	60
	330	23/1	0	14	40
	330	P	0	01	30
	330	P	0	10	26
	330	P	0	10	26
	330	7/3	0	28	84
	330	5/2	0	09	72
	330	P	0	13	86

1	2	3	4	5	6
कोयली निवासी	330	P	0	10	80
	330	P	0	12	40
	330	P	0	08	28
	330	P	0	10	22
	330	P/18/2	0	18	54
	330	P/18/2	0	06	12
अदादरा	79	2	0	50	66
	85	3	0	75	56
	87	1	0	01	50
	59	4	0	10	80
	59	3	0	05	40
	18	1	0	15	29
	835	1	0	02	10
	801	2	0	00	80
	801	3	0	24	39
	802	5	0	06	14

[फ. सं. आर-25011/7/2006-ओ.आर-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

S. O. 3489.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification :

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the (Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

**Schedule**

Tehsil:-Kalol Name of Village	District:-Panchmahal		State :-Gujarat		
	Survey No/Block No	Sub-Division No.	Area		
1	2	3	Hectare	Are	Centiare
Madhvas	111	1	0	03	13
	166	P	0	01	80
	170	1	0	07	06
	101	1P	0	07	47
	166	1P	0	02	81
	166	P2	0	08	10
	211	P2	0	14	76
	211+191+193	P1+P2,P1,1P	0	28	30
	212	1+P2	0	01	30
	236	P1+P2	0	45	76
	269	P2	0	06	83
Jetpur	313	P	0	04	32
	313	P	0	01	50
	308	P	0	15	12
	308	P	0	11	70
	308	P	0	04	68
	308	P1/1	0	08	64
	308	P	0	08	64
	294	P	0	06	12
	109	P	0	15	97
	109	P	0	00	90
	109	P/1	0	11	52
	109	P	0	13	94
	109	P	0	01	89
	108	P	0	05	10
	108	P	0	03	00
	119	P	0	10	17
	125	P	0	13	05
	125	P	0	08	10
	294	2P	0	13	50
	129	P	0	14	40
	129	P	0	09	72
	129	P	0	03	60
	129	P	0	00	68
	129	P2	0	14	85
	153	2	0	18	00
	143	2	0	07	44
	147	2	0	12	24
	147	P1	0	05	04
	147	1P	0	05	72
Kandach	451	1	0	07	77
	294	3	0	01	01

1	2	3	4	5	6
Kandach Con..	295	1	0	05	94
	295	P2	0	05	76
	620	-	0	11	16
	621	2,1	0	10	44
	622	2P4	0	04	50
	622	1P2	0	05	58
	623	7	0	07	56
	624	2	0	09	72
	625	-	0	14	58
	628	-	0	00	80
	623	P	0	12	96
Utarediya	44	1+2	0	02	88
	45	2+3	0	38	32
	94	5	0	10	80
	102	3	0	07	02
	146	1P	0	03	08
	136	1	0	03	42
Vyasda	1194		0	11	70
	1458		0	00	95
Bhukhi	69	3	0	05	58
	86	P	0	01	42
	116	3	0	04	12
	113	3	0	08	10
	112	4	0	05	49
	125		0	03	78
	87	2	0	27	40
Fansi	26	4	0	10	08
	41	3	0	16	02
	44	5	0	03	41
	44	3	0	15	01
	44	3	0	00	10
	6	2	0	04	68
	7	4	0	07	53
	44	2	0	01	10
	44	3	0	09	89
	44	4	0	01	81
	7	2	0	10	62
Karoli	330	Plot20	0	08	96
	330	1P21/2	0	12	14
	330	1P21/3	0	11	79
	330	1P	0	00	24
	330	1-21/1/7	0	00	77
	330	1P	0	12	06
	330	1PPlot164	0	08	36
	330	1P	0	15	84
	330	1P	0	10	98

1	2	3	4	5	6
Karoli Con..	330	1P	0	07	92
	330	1P	0	07	02
	330	1P	0	11	76
	330	1P	0	05	04
	330	1P	0	08	10
	308	1P1	0	22	86
	309	1	0	14	94
	313	2	0	19	88
	330	1P	0	22	60
	330	1P	0	19	44
	320	3	0	09	99
	321	2	0	10	19
	330	1P	0	63	72
	330	1Plot226	0	26	46
	330	1P	0	23	40
	330	plot12	0	00	44
	330	1P	0	29	88
	330	1P	0	00	54
	330	1	0	13	86
	330	1P	0	07	92
	256	2	0	17	64
	255	2/1P2	0	05	76
	330	22/1	0	12	60
	330	23/1	0	14	40
	330	P	0	01	30
	330	P	0	10	26
	330	P	0	10	26
	330	7/3	0	28	84
	330	5/2	0	09	72
	330	P	0	13	86
	330	P	0	10	80
	330	P	0	12	40
	330	P	0	08	28
	330	P	0	10	22
	330	P/18/2	0	18	54
	330	P/18/2	0	06	12
Adadara	79	2	0	50	66

1	2	3	4	5	6
Adadara Con...	85	3	0	75	56
	87	1	0	01	50
	59	4	0	10	80
	59	3	0	05	40
	18	1	0	15	29
	835	1	0	02	10
	801	2	0	00	80
	801	3	0	24	39
	802	5	0	06	14

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]  
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3490.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इककीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं.3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

तालुका : हालोल	जिला : पंचमहल	उप खण्ड सं.	राज्य : गुजरात		
			क्षेत्रफल	हेक्टेयर	एयर
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	वर्ग मीटर		
1	2	3	4	5	6
कंजरी (चन्द्रपुरा)	2354	215/1+2	0	29	88
	2344	203P/1	0	10	11
	2345	214/1+2+3+4	0	25	83
	209	4	0	1	27
	208	3P	0	10	98
	2317+2316	P	0	17	

1	2	3	4	5	6
कोजारी (चन्द्रपुरा) जारी	2316+2317	P	0	15	84
	2355	216/1	0	19	80
	216	2	0	18	18
	2356	224	0	35	58
	2360	P/235/2	0	22	32
	2365	242/2	0	48	6
	225	2	0	21	96
	232	1495	0	17	64
	233	1	0	21	96
मुवाला	78	P3	0	03	85
	78	P	0	34	82
	106	2+2	0	00	10
	102	1+P2	0	03	37
	111	2P	0	00	16
	108	2+1	0	29	88
	109	1+2+3	0	43	68

[फा. सं. आर-25011/7/2006-ओ.आर.-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

**S. O. 3490.**— whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India is available to the general Public, object in writing to the laying of the said pipeline on the land to Comt. Amrit S. Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Ltd., P.O. No. 100, Dholka, Dist. Gandhinagar, Gujarat.

**Schedule**

Tehsil:-Halol	District:-Panchmahal	State :-Gujarat			
Name of Village	Survey No/Block No	Sub-Division No.	Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
Kanjari(Chandrapura)	2354	215/1+2	0	29	88
	2344	203P/1	0	10	11
	2345	214/1+2+3+4	0	25	83
	209	4	0	01	27
	208	3P	0	10	98
	2317+2316	P	0	17	10
	2316+2317	P	0	15	84
	2355	216/1	0	19	80
	216	2	0	18	18
	2356	224	0	35	58
	2360	P/235/2	0	22	32
	2365	242/2	0	48	06
	225	2	0	21	96
	232	1495	0	17	64
	233	1	0	21	96
Muwala	78	P3	0	03	85
	78	P	0	34	82
	106	2+2	0	00	10
	102	1+P2	0	03	37
	111	2P	0	00	16
	108	2+1	0	29	88
	109	1+2+3	0	43	68

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]  
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3491.— केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं. 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूची

तालुका : सावली		जिला : वडोदरा		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.		क्षेत्रफल		
1	2	3	4	हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
पिलोल	714			0	01	54
	1136			0	14	17
	131			0	10	80
ईन्द्राल	1276	4	0	06	48	
	1276	3	0	64	80	
	1276	3	0	57	60	
	775		0	17	73	
	535	P	0	03	71	
	1239		0	06	95	
भेमार	539	2	0	09	93	
	536	P	0	08	19	
	559	2	0	16	18	
	610		0	01	81	
	46	1	0	08	03	
वडदला	114	2P	0	10	98	
	142+141	P	0	25	38	
	140		0	12	60	
	136		0	03	64	
अदलवडा	182	6	0	12	24	
	182		0	04	50	
लोटना	137	23	0	08	10	
	28		0	00	81	
	22		0	31	64	
हरीपुरा	188		0	15	12	
	163		0	18	00	
	164		0	18	90	
	161		0	15	84	
मुढेला	331		0	09	18	

[फ. सं. आर-25011/5/2006-ओ.आर.-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

S. O. 3491.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyal to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

#### Schedule

Tehsil:-Savali	District:-Vadodara		State :-Gujarat		
			Sub-Division No.	Area	
1	2	3	Hectare	Are	Centiare
Pillol	714	-	0	01	54
	1136	-	0	14	17
	131	-	0	10	80
Indral	1276	4	0	06	48
	1276	3	0	64	80
	1276	2	0	57	60
	775	-	0	17	73
	535	P	0	03	71
	1239	-	0	06	95
Vemar	539	2	0	09	93
	536	P	0	08	19
	559	2	0	16	18
	610	-	0	01	81
	46	1	0	08	03
Vadadla	114	2P	0	10	98
	142+141	P	0	25	38
	140	-	0	12	60
	136	-	0	03	64
Adalvada	182	6	0	12	24
	182	-	0	04	50
Lotna	137	23	0	08	10
	28	-	0	00	81
	22	-	0	31	64

1	2	3	4	5	6
Haripura	188	-	0	15	12
	163	-	0	18	00
	164	-	0	18	90
	161	-	0	15	84
Mudhela	331	-	0	09	18

[F. No. R-25011/5/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3492.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रत्लाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इककीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं.3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा -- 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

## अनुसूचा

तालुका : लिसखेडा		ज़िला : दाहोद	राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
खुंदा					
	12	3	0	03	24
	12	2	0	04	55
	12	1	0	02	64
	172	2	0	12	78
	172	3	0	02	20
	18	3	0	10	26
	18	2	0	06	48
	18	1	0	09	36
	14	1	0	01	80
	26	3	0	00	78
	26	5	0	03	60
	26	4	0	00	18
	35	4	0	11	88
	58	P5	0	12	60
	58	P19	0	17	44
	39	P	0	16	56
खीरखाई					
	68	1	0	01	00
	68	2P3	0	14	04
	86		0	48	39
	87	6	0	15	48
	235		0	04	95
	236		0	15	80
	165	1P1	0	24	42
	165	P31	0	09	10
वलुंदी					
	4	P3	0	24	30
	4	P58	0	57	42
पोलीसीमल					
	27	58	0	04	50
	27	P	0	21	06
	27	P11	0	28	14
	27	47/20	0	19	80
	27	45	0	25	20
	27	48	0	23	58
	27	P6	0	09	00
कंबोई					
	40	P14/1	0	16	20
	40	P40/7	0	10	80
	40	P18P/1	0	21	60
	40	P7/3	0	10	26
	40	P7/1P2	0	06	30
	40	56/P1	0	17	92

1	2	3	4	5	6
कंबोई निरंतर	40	P80P1+2	0	28	69
	40	P/75P	0	09	90
	40	P8P1	0	22	00
	40	P/79	0	07	98

[फा. सं. आर-25011/6/2006-ओ.आर-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

S. O. 3492.—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

## Schedule

Tehsil:-Limekheda	District:-Dahod		State :-Gujarat		
	Name of Village	Survey No/Block No	Sub-Division No.	Area	
1	2	3	Hectare	Are	Centiare
Kundha	12	3	0	03	24
	12	2	0	04	55
	12	1	0	02	64
	172	2	0	12	78
	172	3	0	02	20
	18	3	0	10	26
	18	2	0	06	48
	18	1	0	09	36
	14	1	0	01	80
	26	3	0	00	78
	26	5	0	03	60
	26	4	0	00	18
	35	4	0	11	88
	58	P5	0	12	60
	58	P19	0	17	44
	39	P	0	16	56
Khirkhai	68	1	0	01	00
	68	2P3	0	14	04
	86	-	0	48	39
	87	6	0	15	48
	235	-	0	04	95
	236	-	0	15	80
	165	1P1	0	24	42
	165	P31	0	09	10
Valundi	4	P3	0	24	30
	4	P58	0	57	42
Polisimal	27	58	0	04	50
	27	P	0	21	06
	27	P11	0	28	14
	27	47/20	0	19	80
	27	45	0	25	20
	27	48	0	23	58
	27	P6	0	09	00
Kamboi	40	P14/1	0	16	20
	40	P40/7	0	10	80
	40	P18P/1	0	21	60
	40	P7/3	0	10	26
	40	P7/1P2	0	06	30
	40	56/P1	0	17	92

1	2	3	4	5	6
Kamboi Con...	40	P80P1+2	0	28	69
	40	P/75P	0	09	90
	40	P8P1	0	22	00
	40	P/79	0	07	98

[F. No. R-25011/6/2006-O.R.-I]  
S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3493.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं:

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं.3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

तालुका : घोघाबा	जिला : पंचमहल	उप खण्ड सं.	राज्य : गुजरात		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.			
1	2	3	4	5	6
दमवाव	8	1	0	05	40
	115	2/1	0	25	38
	67	1P	0	03	52
	118	1	0	18	90
	37	-	0	32	33
	91	1P	0	05	94
	8	1P	0	04	50
	91	1P9	0	17	82
	91	1P16	0	15	66

1	2	3	4	5	6
सेमालीया	181	1	0	12	60
	699	P	0	24	30
	699	P	0	20	52
	699	P	0	20	28
	699	P	0	02	70
	699	P	0	03	60
	699	P	0	15	30
	699	P	0	26	10
	699	P	0	01	21
	699	P	0	03	78
	699	P	0	09	00
	699	P	0	09	46
	699	P	0	05	70
	699	P	0	10	60
	699	P	0	13	50
	699	P	0	05	58
	99	P	0	09	00
	99	P	0	01	20
	88	P	0	05	40
	108	P	0	01	40
	108	P	0	00	80
	108	P	0	09	77
	108	P	0	04	1
	108	P	0	02	07
	83	P	0	13	50
	82	P	0	01	17
	61	2P	0	11	80
	61	P	0	23	00
	699	P	0	18	90
	699	P	0	00	90
	699	P	0	16	20
	699	P	0	06	30
	699	P	0	08	29
	699	P	0	05	03
	651	2	0	07	74
	652	-	0	01	40
	703	P	0	09	24
	708	1	0	01	00
	702	2	0	20	10
	699	P	0	08	64
	699	P	0	09	37
	699	P	0	11	52
	699	P	0	00	98
	699	P	0	07	92
	699	P	0	21	60
	699	P	0	22	83
	699	P	0	01	65
	699	P35	0	15	18
	144	P	0	10	98
	140	1P	0	08	28
	140	P2	0	07	20

1	2	3	4	5	6
सेमालीया निरंतर...	140	P	0	08	64
	140	P	0	10	62
	100	P4	0	03	96
	100	P4	0	06	12
	100	P4	0	06	66
	100	P5	0	07	20
	99	P	0	06	12
	99	P	0	06	66
खिलोड़ी	22	-	0	19	33
	23	-	0	06	84
	3	-	0	10	85
	17	-	0	25	74
	11	-	0	10	35
	12	1	0	23	76
	12	2	0	13	50
	159	4	0	05	50
	159	2	0	24	84
	158	1	0	12	42
	158	2	0	13	86
	158	3	0	14	76
	169	P	0	32	58
	147	4	0	13	85
	146	4	0	10	02
	159	2	0	05	40
	137	4	0	05	40
खिलोड़ी निरंतर...	137	3	0	06	08
	137	2	0	05	40
	137	1	0	06	30
	138	P	0	06	30
	138	P	0	09	00
	139	-	0	18	28
	139	P	0	00	35
	140	2	0	07	47
	140	2A	0	11	70
	123	P	0	23	91
	122	-	0	19	80
	121	-	0	15	44
शेरपुरा	85	P	0	06	12
	85	P	0	14	58
	85	P	0	09	54
	59	1P2	0	01	17
	59	1P	0	21	25
	60	P	0	12	78
	61	-	0	00	90
	47	P2	0	05	76
	47	1P	0	03	96
	43	2	0	01	82
	26	4	0	02	00
	19	1	0	07	47
	189	6	0	02	24
	189	3	0	07	01

New Delhi, the 7th December, 2007

**S. O. 3493.—**whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

**Schedule**

Tehsil:-Ghoghambha			District:-Panchmahal			State :-Gujarat		
Name of Village			Survey No/Block No	Sub-Division No.	Area			
1	2	3			Hectare	Are	Centiare	
1	2	3	4	5	6			
Damvav	8	1	0	05	40			
	115	2/1	0	25	38			
	67	1P	0	03	52			
	118	1	0	18	90			
	37	-	0	32	33			
	91	1P	0	05	94			
	8	1P	0	04	50			
	91	1P9	0	17	82			
	91	1P16	0	15	66			
Semaliya	181	1	0	12	60			
	699	P	0	24	30			
	699	P	0	20	52			
	699	P	0	20	28			
	699	P	0	02	70			
	699	P	0	03	60			
	699	P	0	15	30			
	699	P	0	26	10			
	699	P	0	01	21			
	699	P	0	03	78			
	699	P	0	09	00			

1	2	3	4	5	6
Semaliga Con...	699	P	0	09	46
	699	P	0	05	70
	699	P	0	10	60
	699	P	0	13	50
	699	P	0	05	58
	99	P	0	09	00
	99	P	0	01	20
	88	P	0	05	40
	108	P	0	01	40
	108	P	0	00	80
	108	P	0	09	72
	108	P	0	04	14
	108	P	0	02	07
	83	P	0	13	50
	82	P	0	01	17
	61	2P	0	11	80
	61	P	0	23	00
	699	P	0	18	90
	699	P	0	00	90
	699	P	0	16	20
	699	P	0	06	30
	699	P	0	08	29
	699	P	0	05	03
	651	2	0	07	74
	652		0	01	40
	703	P	0	09	24
	708	1	0	01	00
	702	2	0	20	10
	699	P	0	08	64
	699	P	0	09	37
	699	P	0	11	52
	699	P	0	00	98
	699	P	0	07	92
	699	P	0	21	60
	699	P	0	22	83
	699	P	0	01	65
	699	P35	0	15	18
	144	P	0	10	98
	140	1P	0	08	28
	140	P2	0	07	20
	140	P	0	08	64
	140	P	0	10	62
	100	P4	0	03	96
	100	P4	0	06	12
	100	P4	0	06	66
	100	P5	0	07	20
	99	P	0	06	12
	99	P	0	06	66
Khilodi	22	-	0	19	33
	23	-	0	06	84
	3	-	0	10	85
	17	-	0	25	74

1	2	3	4	5	6
Khilodi Con..	11	-	0	10	35
	12	1	0	23	76
	12	2	0	13	50
	159	4	0	05	50
	159	2	0	24	84
	158	1	0	12	42
	158	2	0	13	86
	158	3	0	14	76
	169	P	0	32	58
	147	4	0	13	85
	146	4	0	10	02
	159	2	0	05	40
	137	4	0	05	40
	137	3	0	06	08
	137	2	0	05	40
	137	1	0	06	30
	138	P	0	06	30
	138	P	0	09	00
	139	-	0	18	28
	139	P	0	00	35
	140	2	0	07	47
	140	2A	0	11	70
	123	P	0	23	91
	122	-	0	19	80
	121	-	0	15	44
Sherpura	85	P	0	06	12
	85	P	0	14	58
	85	P	0	09	54
	59	1P2	0	01	17
	59	1P	0	21	25
	60	P	0	12	78
	61	-	0	00	90
	47	P2	0	05	76
	47	1P	0	03	96
	43	2	0	01	82
	26	4	0	02	00
	19	1	0	07	47
	189	6	0	02	24
	189	3	0	07	01

[F. No. R-25011/7/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3494.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं. 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

तालुका : दाहोद		जिला : दाहोद		राज्य : गुजरात		
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	क्षेत्रफल			
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर	
1	2	3	4	5	6	
रामपुरा	1	5A3	0	85	32	
कालीतलाई	59		0	48	00	
बोरवानी	139		0	11	20	
खरोड	301	106P	0	28	08	
	301	104	0	14	49	
	301	101P	0	35	73	
खरेडी	78	2	0	08	82	
	94	P	0	11	59	
	96		0	00	59	
	120		0	00	92	
	117		0	18	90	
	122		0	11	03	
	123		0	25	58	
	124		0	07	14	
	134		0	18	96	
	133		0	17	70	
	132		0	26	53	
	131		0	14	65	
	203		0	18	26	
	204		0	15	22	
	206		0	30	13	
	208		0	17	27	
	209		0	15	74	
	210		0	15	29	
	211		0	10	62	

1	2	3	4	5	6
नानोराणापुर	124		0	25	86
	131	2	0	61	73
	128	1	0	02	37
	132		0	14	04
	133		0	02	04
	6	3	0	10	26
	6	2	0	18	36
	7		0	05	02
	8		0	20	25
	26	1A	0	19	10
	25	-	0	09	98
	24	1	0	08	10
	22	-	0	13	19
	21	-	0	10	98
	20	-	0	23	73
नवागाम	377	-	0	28	07
	263	-	0	02	41
	284	-	0	19	84
	319	10	0	17	78
	319	9	0	03	93
	319	11	0	13	03
	392	2	0	11	26
	391	2	0	14	03
	399	2	0	07	12
	413	-	0	01	25
	432	P	0	09	15
	431	P	0	26	48
तानाचीया	69	-	0	01	38
	40	2P	0	44	64
राचरडा	266	-	0	00	67
भाटीवाडा	137	-	0	47	98
	141	-	0	07	14
	142	-	0	24	47
	143	-	0	10	80
	152	-	0	35	65
	153	-	0	05	49
उदार	15	-	0	05	19
	58	2/14	0	08	40
	58	2/13	0	20	06

[फ. सं. आर-25011/6/2006-ओ.आर.-I]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

**S. O. 3494.**—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

**Schedule**

Tehsil:-Dahod	District:-Dahod		State :-Gujarat		
			Survey No/Block No	Sub-Division No.	Area
1	2	3	4	5	6
Rampura	1	5A3	0	85	32
Kalitalai	59	-	0	48	00
Borwani	139	-	0	11	20
Kharod	301	106P	0	28	08
	301	104	0	14	49
	301	101P	0	35	73
Kheredi	78	2	0	08	82
	94	P	0	11	59
	96	-	0	00	59
	120	-	0	00	92
	117	-	0	18	90
	122	-	0	11	03
	123	-	0	25	58
	124	-	0	07	14
	134	-	0	18	96
	133	-	0	17	70
	132	-	0	26	53
	131	-	0	14	65

1	2	3	4	5	6
Kheredi(Con.)	203	-	0	18	26
	204	-	0	15	22
	206	-	0	30	13
	208	-	0	17	27
	209	-	0	15	74
	210	-	0	15	29
	211	-	0	10	62
Naniranapur	124	-	0	25	86
	131	2	0	61	73
	128	1	0	02	37
	132	-	0	14	04
	133	-	0	02	04
	6	3	0	10	26
	6	2	0	18	36
	7	-	0	05	02
	8	-	0	20	25
	26	1A	0	19	10
	25	-	0	09	98
	24	1	0	08	10
	22	-	0	13	19
	21	-	0	10	
	20	-	0	23	73
Navagam	377	-	0	28	07
	263	-	0	02	41
	284	-	0	19	84
	319	10	0	17	78
	319	9	0	03	93
	319	11	0	13	03
	392	2	0	11	26
	391	2	0	14	03
	399	2	0	07	12
	413	-	0	01	25
	432	P	0	09	15
	431	P	0	26	48
Tanachiya	69	-	0	01	38
	40	2P	0	44	64
Racharda	226	-	0	00	67
Bhatiwada	137	-	0	47	98
	141	-	0	07	14
	142	-	0	24	47
	143	-	0	10	80
	152	-	0	35	65
	153	-	0	05	49
Udar	15	-	0	05	19
	58	2/14	0	08	40
	58	2/13	0	20	06

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2007

का. आ. 3495.—केन्द्रीय सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि गुजरात राज्य में कोयली से रतलाम तक पेट्रोलियम उत्पादन के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, एक पाइपलाइन बिछाई जानी चाहिए;

और केन्द्रीय सरकार को उक्त पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें उक्त पाइपलाइन बिछाए जाने का प्रस्ताव है और जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचि में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं;

कोई व्यक्ति, जो उक्त अनुसूचि में वर्णित भूमि में हितबद्ध हैं, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, इक्कीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाए जाने के संबंध में श्रीमती आशा आर. शाह, सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड, मकान नं. 3/122, गुजरात रिफाइनरी टाउनशिप, पो.ओ. जवाहरनगर, वडोदरा – 391 320 (गुजरात) को लिखित रूप में आक्षेप भेज सकेगा।

### अनुसूची

तालुका : बारिया	जिला : दाहोद	उप खण्ड सं.	राज्य : गुजरात		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
गाँव का नाम	सर्वेक्षण सं. - खण्ड सं.	उप खण्ड सं.	4	5	6
1	2	3			
मोतीझरी	192		0	17	53
	33	1+2	0	09	59
	4	1	0	05	11
	4	2	0	28	11
	7	2	0	07	40
पिपलोद	234		0	28	08
	240	1	0	12	14
	582		0	23	40
	571	2	0	20	82
पन्चेला	97	P2	0	26	83
	89	5	0	19	08
	88	1	0	11	16
	88	3	0	10	80
	88	5	0	02	61
	88	4	0	10	00
नानुडी	7	-	0	33	30

[फा. सं. आर-25011/6/2006-ओ.आर-1]

एस. के. चिटकारा, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2007

**S. O. 3495.**—whereas it appears to the Central Government that it is necessary in the Public interest that for the transportation of Petroleum Products from Koyali to Ratlam in the State of Gujarat, a pipeline should be laid by the Indian Oil Corporation Limited;

And whereas it appears to the Central Government that for the Purpose of laying the said pipeline, it is necessary to acquire the right of user in the land under which the said pipeline is proposed to be laid and which is described in the Schedule annexed to this notification ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section 3 of the Petroleum and Minerals (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50of 1962), the Central Government hereby declares its intention to acquire the right of user therein ;

Any person interested in the land described in the said Schedule may, within twenty one days from the date on which the copies of the notification issued under sub-section (1) of section 3 of the said Act, as Published in the Gazette of India are made available to the general Public, object in writing to the laying of the pipeline under the land to Smt. Asha R Shah, Competent Authority, Indian Oil Corporation Limited , at office Qtrs. No. 3/122, Gujarat Refinery Township, P.O. Jawaharnagar, Vadodara – 391320 (Gujarat)

**Schedule**

Tehsil:-Bariya Name of Village	District:-Dahod Survey No/Block No	Sub-Division No.	State :-Gujarat Area		
			Hectare	Are	Centiare
1	2	3	4	5	6
MotiZari	192	-	0	17	53
	33	1+2	0	09	59
	4	1	0	05	11
	4	2	0	28	11
	7	2	0	07	40
Piplod	234	-	0	28	08
	240	1	0	12	14
	582	-	0	23	40
	571	2	0	20	82
	97	P2	0	26	83
Panchela	89	5	0	19	08
	88	1	0	11	16
	88	3	0	10	80
	88	5	0	02	61
	88	4	0	10	00
	7	-	0	33	30
Nathudi					

[F. No. R-25011/6/2006-O.R.-I]

S.K. CHITKARA, Under Secy.

**श्रम एवं रोजगार मंत्रालय**

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3496 :**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ संख्या-1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 38/1999) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/236/1995-आई.आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**

New Delhi, the 20th November, 2007

**S.O. 3496 .**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 38/1999) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of State Bank of India, and their workmen, received by the Central Government on 20-11-2007.

[No. L-12012/236/1995-IR (B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI SANT SINGH BAL PRESIDING  
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT NO. 1**

**NEW DELHI**

**I.D. NO. 38/99**

In the matter of dispute between :—

Shri Subhash Kapoor,  
S/o Late Shri Santosh Lal Kapoor  
Through The Circle President,  
S.B.I. Staff Association,  
Hari Singh Nalwal Street No.58,  
Karol Bagh. .... Workman

Versus

The General Manager (Planning),  
State Bank of India,  
Local Head Office ,  
11, Sansad Marg ,  
New Delhi- 110001. .... Management

**Appearances :** Shri S.K.Patni A/R for workman  
Shri Anil Kumar Beheti, Law Officer  
for management.

**AWARD**

The Central Government in Ministry of Labour vide

its Order No. L-12012/236/95/I.R.(B-I) dated 3-3-97 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of State Bank of India in discharging Shri Subhash Kapoor clerk, from service w.e.f. 16-7-93 and stoppage of pension is just, fair and legal ? If not what relief the concerned workman is entitled to?”

2. Brief facts of this case as culled from record are that the workman Shri Subhash Kapoor was appointed on 8-1-1970 as Clerk and was discharged from service w.e.f. 16-7-93 after putting total service of 23 years 6 months and 8 days. The service conditions of the Award Staff of the respondent (including clerical cadre staff) are governed by the Sastry Award as modified by the Desai Award and subsequent Bipartite Settlements. The workman was working as Clerk in the bank at Organisational Planning Department, New Delhi, Local Head Office. His wife was running a Video Library at her residence. The police allegedly seized some alleged obscene material from the Video Library and the Police wanted to take into custody the workman’s wife. To avoid social stigma and under pressure from his relations he admitted alleged guilt of running the library to save his wife from the clutches of law. The workman was released on probation by the court of Shri Rakesh Garg, M.M., Patiala House, New Delhi on 17-7-92 under Section 12 of the Probation of Offenders Act, 1958. The workman duly informed the bank that he was released on probation by the court. The Bank ignoring the provisions of S. 12 of the Probation of Offenders Act issued a show cause notice to the workman vide its letter No. 1620 dated 26-11-92 as to why he should not be dismissed from Bank Service with immediate effect under Section 520/521 (2) (b) of the Sastry Award, relevant provisions of the Desai Award and other agreements applicable to Award Staff and also in terms of Section 10 (1)(b)(i) of Banking Regulation Act 1949. He submitted his reply to the notice vide letter dated 31-12-92 but he was proceeded departmentally and illegally discharged from service w.e.f. 16-7-93 with stoppage of pension vide order dated 14-10-93 by Disciplinary Authority without holding proper enquiry which punishment was confirmed in appeal. The dismissal order was illegal and contrary to the provisions of the Sastry Award, Desai Award, Bipartite Settlement and relevant rules and it was passed without taking into consideration the fact that he was released on probation under section 12 of Probation of Offenders Act. He thus sought the quashment of order dated 14-10-93 discharging him from service with reinstatement and consequential benefits etc.

3. Claim has been contested by the management justifying the action of the bank as legal.

4. Written statement was followed by rejoinder wherein controverted facts of the written statement were refuted and those of the claim statement were reiterated to

be correct.

5. Thereafter evidence of the parties were adduced. Shri T.D. Arora, Assistant General Manager State Bank of India Office Admn. Deptt. was examined on behalf of the management as MWI and workman examined himself as WWI in support of his case.

6. After close of evidence Sh S.K. Patni A/R for the workman and Shri Anil Kumar A/R for the management addressed arguments and also filed written submissions with citations.

7. A/R for the workman contended that the action of the bank in illegal and unjustified and his releasing on probation should be taken into account to reinstate him in service with full back wages and the punishment is also very harsh. He has also challenged the order of punishment as harsh and disproportionate in the facts and circumstances of the case.

8. A/R of the management refuted the above contentions justifying discharge of the workman from service in the background of confession of his guilt before the Criminal Court requiring no regular enquiry.

9. I have given my thoughtful consideration to the contentions raised on either sides and perused the record meticulously.

10. In the instant case it is admitted fact that the claimant himself confessed the fact before the Criminal court that he owned the video library containing obscene cassette etc. which amounted to an offence of section 292 I.P.C. and on his confession he was convicted and released on probation under section 12 of probation of offenders Act. In view of confession of his guilt, his contention that no regular enquiry was conducted by the disciplinary authority and the punishment of moral turpitude on the basis of his admission is illegal is of no value.

11. As regards his contention that no departmental enquiry was required to be conducted for misconduct in view of his release on probation by the criminal court it may be pointed out that this contention is not tenable in view of the decision of the Supreme Court reported in U.O.I Vs. Bakshi Ram 1990 Supreme Court Cases page 426 wherein it was held that the release of a person under section 12 of probation of offenders Act does not preclude department from taking action for misconduct leading to the offence or his conviction thereon as per law. This Section was not intended to exonerate the person from departmental punishment. It only directs that the offender shall not suffer disqualification, if any, attaching to a conviction of an offence under such law. Release of a Government servant on probation under section 12 of the Probation of Offenders Act by the Criminal Court does not grant him any protection against being proceeded departmentally for his misconduct. In view of the above discussion taking into consideration the facts and circumstances of the above case I am of the opinion that the retention of the workman in service will not be proper and action of the management is just, proper and legal.

12. I have also heard the A/R for the workman on the point of punishment. It has been urged that the punishment

afforded to the workman is very harsh and he has been deprived of his pension despite the fact that he has put in 23 years of service. Taking into consideration the fact that the workman has put in 23 years of service, punishment of depriving him of the pension appears to be harsh. Hence interest of justice will be met if the punishment of discharge is altered and lenient view is taken in the matter of stoppage of pension only. It would be proper if the workman is compulsorily retired from service with benefits of pension. It is ordered accordingly and Award is thus passed. File be consigned to record room.

SANT SINGH BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2007

का. आ. 3497 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी.पी. डब्ल्यूडी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.-1, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 61/94) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/187/93-आई.आर.(डी यू)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 20th November, 2007

S.O. 3497.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 61/94) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of C.P.W.D. and their workmen which was received by the Central Government on 20-11-2007.

[No. L-42012/187/93-IR (D U)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI SANT SINGH BAL PRESIDING  
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1  
NEW DELHI

I.D. NO. 61/94

In the matter of dispute between :—

Smt. Savitri Devi,  
House No. 5/61, Trilok Puri,  
Delhi- 110092.

... Workman

Versus

Central Public Works Department  
Through Executive Engineer (Elect.)  
K.Division, CPWD,  
Indraprastha Estate,  
New Delhi- 110002.

... Management

Appearances : None

**AWARD**

The Central Government, in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/187/93-I.R.(DU) dated 5-5-94 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of Executive Engineer, ‘K’ Division, C.P.W.D. and Canteen Manager CPWD, ‘Y’ Shape Building New Delhi in terminating the services of Smt. Savitri Devi, Bearer of CPWD departmental canteen w.e.f. 1-2-93 is justified ? If not, what relief the workman concerned is entitled to?”

2. After completion of pleadings and evidence of the parties case was adjourned for filing of written arguments by the parties on 20-5-97 and till today none is appearing for the workman Smt. Savitri Devi she last appeared in this case on 9-3-2001. Thereafter neither workman nor anybody on her behalf appeared on 21-5-2001, 21-5-2001, 14-8-2001, 19-10-2001, 15-1-2002, 18-4-2002, 3-9-2002, 3-12-2002, 3-3-2003, 22-5-2003, 5-8-2003, 17-11-2003, 5-2-2003, 27-4-2004, 29-7-2004, 19-10-2004, 25-1-05, 20-4-06, 29-6-05, 21-9-2005, 26-12-05, 21-3-06, 8-6-06, 19-9-06, 27-9-06, 22-11-06, 31-1-07, 22-3-07, 30-7-07, and today on 30-10-07 also none is present for the parties. Hence No Dispute Award is passed in this case. File be consigned to record room.

Dt. 5-11-07

SANT SINGH BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2007

का. आ. 3498 :—ऑद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नार्दन रेलवे के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट ऑद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण सं.-1 चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 20/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41011/53/2004-आई.आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd November, 2007

**S.O. 3498** .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 20/2007) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, I Chandigarh, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Northern Railway, and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-41011/53/2004-IR(B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,  
CHANDIGARH

Case No. I. D. 20/2007

1. Sh. H. K. Sharma Secretary, Uttariya Rialway Karamchari Union, EF- 430, Krishan Nagar, N. G. Road Jalandhar (Punjab).

2. The General Secretary, All India French Bank Employees' Co-ordination Committee, C/o Banque Nationale De Paris, French Bank Building, 62, Homji Street, Fort, Mumbai-400001.

... Applicant

1. The General Manager, Northern Railway, Baroda House, New Delhi.

2. The Divisional Manager, Northern Railway, Ferozepur.

3. The Head HR, BNP Paribas French Bank Building, 62, Homji Street-Fort, Mumbai-400001.

... Respondent

**APPEARANCES**

For the Workmen : None.

For the Management : Shri N. K. Zakhmi.

**AWARD**

Passed on 16-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-41011/53/2004/IR (B.I.) dated 14-2-2007 has referred the following dispute to his Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of Northern Railways in not placing 15 employees (List enclosed) in the grade of Rs. 1400—2300 w.e.f. 1-3-93 i.e. date of restructuring of their cadre is just and legal? If not, to what relief these workers are entitled to and from which date?”

2. Case repeatedly called. None has put up appearances on behalf of the Union i.e. H.K. Sharma, Secretary, Uttariya Railway Karamchari Union and the General Secretary, All India French Bank Employees Coordination Committee who raised the demand despite notices for 28-5-07, 10-7-07, 23-8-07 and for 27-9-07 through Regd. notices as well as simple notice, and none has put up appearances on behalf of the Union for today also. It appears that Union is not interested to pursue with the present reference. In view of the above, the present reference is returned to the Central Govt. for want of prosecution. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

16-10-07

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2007

का. आ. 3499 :—ऑद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट ऑद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 110/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/33/2005-आई.आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd November, 2007

**S.O. 3499** .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 110/2005) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of State Bank of India, and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-12012/33/2005-IR (B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
JABALPUR**

**NO. CGIT/LC/R/110/05**

Presiding Officer : Shri C. M. Singh

The General Secretary,  
Daily Wages Bank Employees Association,  
9, Sanwar Road, Ujjain (MP)  
Ujjain. .... Workman/Union

Versus

The Deputy General Manager,  
State Bank of India,  
Zonal Office, Hamidia Road,  
Bhopal (MP),  
Bhopal. .... Management

**AWARD**

Passed on this 31st day of October, 2007

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-12012/33/2005-IR(B-I) dated 29/9/05 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:

“Whether the action of the management of Dy. General Manager, State Bank of India in terminating the services of Sh. Indraraj Singh Baakriaya w.e.f. 16-10-99 and not regularizing him is justified? If not, to what relief workman is entitled for?”

2. Shri R. Nagwanshi, General Secretary, Dainik Vetan Bhogi Bank Karmachari Sangathan, Ujjain (MP) has moved application No.5 with the prayer that No Dispute Award be passed in this case.

3. In this case, the management has not put in appearance inspite of issuing notice to management.

4. The reference order reveals that this reference has been instituted on the initiation of the General Secretary, Dainik Vetan Bhogi Bank Employees Association, 9, Sanwar Road, Ujjain(MP). Now the said General Secretary does not press the reference and requested in writing for passing no dispute award.

5. In view of the above, no dispute award is passed without any orders as to costs.

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2007

का. आ. 3500 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार वेस्टर्न रेलवे के प्रबंधालय के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 128/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-41012/52/2001-आई.आर.(बी-1)]

अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd November, 2007

S.O. 3500 .—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award

(Ref. No. 128/2001) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, Jabalpur, as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Western Railway, and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-41012/52/2001-IR(B-1)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,  
JABALPUR**

**NO. CGIT/LC/R/128/01.**

Presiding Officer : Shri C. M. Singh

Shri Roop Singh Dalla,  
Rly.Qtr.No. 1572,  
Road No.14, Rly.Colony,  
Ratlam (MP) .... Workman/Union

Versus

The Divisional Railway Manager,  
Western Railway,  
Near Railway Station,  
Ratlam (MP) .... Management

**AWARD**

Passed on this 5th day of November, 2007

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-41012/52/2001(IR-B-1) dated 28-7-01 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal :

“Whether the action of the management of DRM, Western Railway, Ratlam in not giving the regular appointment to Shri Roop Singh even after empanelment is justified? If not, to what relief the workman is entitled for?”

2. Vide order dated 30-10-07 passed on the order sheet of this reference, the reference proceeded ex parte against the workman. The workman did not file any statement of claim.

3. On 2-11-07, the date fixed for filing Written Statement by the management, no body put in appearance for the management and thus the management has failed to file the WS. Under the circumstances, this tribunal was left with no alternative but to close the reference for award and accordingly the reference was, therefore; closed for award.

4. It is a case without pleadings of the parties and evidence of the parties. Therefore the case deserves to be decided in favour of the management and against the workman without any orders as to costs.

5. In view of the above, the reference is decided in favour of the management and against the workman without any orders as to costs holding that the action of the management of DRM, Western Railway, Ratlam in not giving the regular appointment to Shri Roop Singh even after empanelment is justified and consequently the workman is not entitled to any relief.

6. Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3501 :**—ओद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार न्यू इंडिया कोपरेटिव बैंक लि.के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट ओद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार ओद्योगिक अधिकरण सं. 2 मुम्बई के पंचाट (संदर्भ संख्या 91/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/286/2002-आई. आर.(बी-1)]  
अजय कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 23rd November, 2007

**S.O. 3501 .—**In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 91/2002) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, Mumbai as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of New India Co-operative Bank Ltd., and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-12012/286/2002-IR(B-I)]

AJAY KUMAR, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS- TRIAL TRIBUNAL No.2, MUMBAI

#### PRESENT

A. A. Lad, Presiding Officer

Reference No. CGIT-2/91 of 2002

#### Employers in Relation to the Management of New India Co-Operative Bank Limited

The General Manager (Personnel)  
New India Co-operative Bank Ltd.  
241/243, P. D. Mello Road  
Fort,  
Mumbai-400 001.

AND

#### Their Workmen

Shri Prakash Dalvi,  
'B' Wing, Vaibhav Apartments,  
Bhandar Galli, L.J. Road,  
Mahim,  
Mumbai 400 016.

#### APPEARANCES

For the Employer :	Mr. Shridhar Poojary, Advocate
For the Workmen :	Ms. Kunda N. Samant, Advocate.

Mumbai, dated 4th October, 2007

Ref.CGIT 2/91 of 2002

#### AWARD

Matrix of the facts as culled out from the reference are as under :

1. The Government of India, Ministry of Labour, by its Order No.L-12012/286/2002[IR(B-I)] dated 18-12-2002 in exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 have referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of New India Cooperative Bank, Mumbai by orally terminating the services of Shri Prakash Dalvi w.e.f. 17-08-1999 is justified? If not, what relief the workman Shri Prakash Dalvi is entitled to?"

2. Claim statement is filed at Ex-7 in support of the demand by the concerned workman making out case that, initially he was appointed as a Peon on 16-01-1982. He was attending all sort of outside work connected with first party Bank. He was also doing work of maintaining record of signature of Savings slips. He was visiting the taxi men's union to collect the cheques of deposits and was stitching the bunches of vouchers, stapling it as well as doing dispatching work. He worked upto 22-09-1984 in that fashion from 16-01-1982.

3. On 22-9-84 when he left for work of first party to board train at Byculla Station, he sustained injury. Said accident took place when he was in the employment of first party. That time he was proceeding to RBI regarding work of the first party. He was admitted in Saba Saheb Ambedkar Hospital by Railway Authority. In the operation, his lower portion below left knee was removed. Railway authority gave Rs. 60,000/- as compensation. However no steps were taken by first party to award compensation or to enquire about his position. He tried to contact first party through leader of Union and requested atleast to take any of his family member on Compassionate ground. However, it was not considered by the Bank.

4. He resumed on duty after the accident and he was transferred from various places including Andheri, Goregaon, Bandra, still he performed his duties which were assigned to him and like that he worked for 16 years.

5. From 22-11-98 he suffered from diabetics and was admitted in Radhabhai Waturnal Hospital. Dr. Vivek N.

Allahabadla was giving treatment when he was in the hospital and due to mistake of Ward boy, concerned workman fell down while he was shifted and as such, suffered injury in right leg which was operated and was taking treatment on it upto July 1999. For that, he sent medical certificate to first party to regularise his leave from 22-11-98 till he was declared fit i.e., June 1999. However his leave was not considered though salary was paid upto June 1999.

6. As a result of said accident, he was in depressed state of mind. He wrote letter to Chairman to take any other member of his family on compassionate ground mentioning name of wife who was educated upto 8th std. However it was not considered by Bank and Chairman of it. He was called before Panel of Doctors of the first party. He faced it. However he was declared unfit and first party decided to terminate his services on that ground w.e.f. 17-08-1999. According to second party, he was fit to attend the work which was assigned to him. Even Doctor declared him fit. He was 44 years old and 14 years were at his credit to serve. Bank did not consider it and disciplinary authority decided to terminate his services on medical ground without following due process of law or by giving retirement compensation and other legal dues. So it is prayed that, decision taken by first party w.e.f. 17-8-99 be declared not just and proper and direct first party to reinstate him with backwages and continuity of service.

7. During the pendency of the reference, second party workman died on 23-01-2007. By purshis Ex-42 heirs of second party prayed to bring their name in place of deceased workman to claim legal dues.

8. This claim is disputed by first party by filing reply Ex-8 making out case that, concerned workman was not fit to continue since he lost his ability of work when he met with the accident. Even he was on continuous leave on medical ground which reveals that he is not fit. Even Doctor opined that his disability is 60% which does not permit such a person to declare fit to work. When he is not fit, question of following provisions of Industrial Disputes Act does not arise since said termination does not fall under Section 2 (oo) of Industrial Disputes Act. It is stated that, prayer prayed by concerned workman to take his wife on employment on compassionate ground has no any base. There is not settlement between first party and Union to consider such claim. Even Bank informed accordingly. It is denied that, decision taken by first party of retrenching second party on medical ground is not just and proper. According to first party, relying on the opinion of the panel of doctors to examine second party and declare workman unfit and observing 60% disability was base behind termination and decision was taken on it is just and proper and does not require interference.

9. As far as bringing legal heirs on record of deceased workman is concerned, it is not disputed by first

party and as a result of that, prayer of second party subsist to consider as far as his claim regarding re-employment or treating him as employee from 17-8-99 till he died subsist.

10. In view of above pleadings, my learned Predecessors framed issues at Ex-15 which I answer against it as follows :

Issues	Findings
i. Whether the workman proves that he was retrenched without following the provisions of Section 25 F of the Industrial Disputes Act.	Yes.
ii. Whether the action of the management of New India Co-operative Bank, Mumbai by terminating the services of Shri Prakash Dalvi w.e.f. 17-8-99 on the ground of continued ill health is justified?	No.
iii. What relief the workman is entitled to? Heirs of second party are entitled for existing wages of deceased workman at the rate of the time of termination i.e. on 17-08-1999, w.e.f. 17-08-1999 till 23-01-2007.	
iv. Whether the workman proves that he is able to perform the same duties performed by him since 1984 to November 1998? Does not survive.	

#### REASONS

##### Issue Nos : 1, 2 & 3 :

11. Deceased second party workman claims that, he was terminated without following due process of law though he was admittedly disabled person. According to second party, after meeting with the accident he reported on duty and was doing work assigned to him. As far as working on the post even after accident and doing duties assigned to him are concerned, there is not dispute about it. Bank has raised dispute about his ability of work after he met with accident second time when he was taking treatment on diabetics from Dr. Allahabadi i.e. till he fell down while he was shifted by the ward boy on 22-11-98. As far as physical condition of second party is concerned and work assigned to him after he met with railway accident till the period of 22-11-98 is concerned, there was no any serious dispute. It is admitted position that, deceased workman joined on 16-01-1982 and met with Railway accident on 22-09-1984 and even thereafter he was there in the employment of first party and was attending duties assigned to him till 22-11-1998.

13. The say of the deceased workman is that, even after meeting with accident 2nd time, while he was taking treatment on diabetics, he was recovered and was fit to work. However first party decided to terminate his employ-

ment relying on the opinion of Panel Doctors which is not just and proper. To support that, second party's advocate place reliance on the citation published in 1992 II LLJ page 439. While deciding case of Lalit Mohan Puri V/s. Pure Drinks (New Delhi) Ltd., Delhi High Court observed that, employer cannot act on the basis of presumptions. In the said case (Supra), the petitioner of the case was in the employment of the Pure Drinks (New Delhi) Ltd. He served for 16 years. He was salesman and was driving vehicle to sell Coca Cola and other soft drinks. He was asked to drive heavy vehicle to which he refused and charge sheet was served asking to reply within 48 hrs. Said charge sheet was replied pointing out his case. It was not liked by the employer and so action was taken without holding enquiry and termination was affect which is treated illegal by Delhi High Court. Another Citation referred published in 1990 II CLR where Apex Court while deciding case of Puniab Land Development & Reclamation Corporation Ltd., Chandigarh & Ors. V/s. Presiding Officer, Labour Court, Chandigarh observed that, retrenchment means termination by employer where provision of Industrial Disputes Act required to be followed before effecting such a termination. Citation published in 1995 II LLJ page 716 reveals that, while deciding case of Rameshwar Dass & Ors. etc. V/s. State of Haryana, Apex Court observed that employer has to assists the possibility of providing alternative job and without it management cannot take decision of termination declaring employee unfit. Citation referred published in 2006 I LLJ 480 reveals that, request of disabled employee to given alternative work without giving proper consideration if rejected, such employee is entitled to reinstatement. Citation referred published in 1992 LAB IC page 451 where Orissa High Court observed that, continuous ill health cannot be assumed without hearing concerned workman and management cannot take action simply relying on it and terminate employee. Whereas first party's advocate place reliance on the Citation published in 1991 I CLR page 525 where Apex Court while deciding Anand Bihari & ors. V/s. Rajasthan State Road Transport Corporation & Anr. observed that, if there is any disorder in health which incapacitates an individual from discharging duties, in that case if decision of termination is taken it is just and proper. However facts of that case and facts of the case which is at hand are different. In the above case (Supra) employer after issuing notice and issuing charge sheet, consider the explanation of workman and then it took decision of that type which is observed just and proper. However in the instant case at hand no such notice issued nor show-cause notice. There was no hearing of second party on that. No chargesheet given. No explanation sought. So definitely such a decision taken in such case was not decision as taken in Anand Bihari Case. Even first party's advocate place reliance on citation published in 2005 III CLR 120 where Bombay High Court while deciding case of

Ramaswamy Murugesh Vrs. S.G. Bhosale, the then Presiding Officer, 5th Labour Court & Anr observed that, if workman is suffering from continuous ill health and there was evidence on that point, there is no illegality In upholding the decision of termination. However in the said case also workman involved in that case was absent for number of days and produced medical certificate. He was on leave on ground of illness issuing medical certificates and was asked to visit after 15 days. Then he was asked to show improvement in his work and when it was seen no improvement in work, he was terminated. In case at hand no such opportunity was given to second party workman and action taken on presumption was not an action taken in case of Ramaswamy which was upheld by Hon'ble Bombay High Court. The Citation published in 1999 I CLR 780 referred where again Bombay High Court while deciding case of Ceat Ltd. Vrs. observed that, the award given by Labour Court suffered from serious infirmity on account of invoking a non-existent concept. For example termination only on ill health which is not a law. However in that case also workman involved remained absent for number of days, was asked to report on duty then charge sheet was served, explanation was sought and then decision was taken. Whereas in the instant case, no such opportunity was given to workman.

14. So if we considered all this, coupled with discussions made above, I conclude that, no opportunity was given to concerned workman to show his ability which required to give. No charge sheet was served. No inquiry was conducted. Employer sits on the opinion of panel Doctors as evidence and decided to terminate services of second party which is not just, proper and require to quash.

15. Second party was terminated on 17-08-1999 without following due process of law. As per purshis Ex-42 he died on 23-01-2007. It is to be noted that, he was of 44 years when he was terminated. So definitely I have to observe that he was fit to work till 23-01-2007 and entitled to get benefits of backwages presuming that, he was eligible to work and presuming that, he worked for the Bank till his death i.e. 23-01-2007 as a result of that, his legal heirs are entitled to get salary of the deceased workman from 17-08-1999 with all benefits available to that post from 17-08-1999 to 23-01-2007.

16. It is to be noted that, this second party workman died on 23-01-2007, so question of his reinstatement does not arise. Besides, prayer prayed by concerned workman to take his legal heirs in the employment on compassionate ground is also not proved by reproducing any settlement which took place between union and first party. That means second party has to establish the right of heirs of deceased who can claim employment on compassionate ground. It is matter of record that, no any compensation was given by first party to the concerned workman when he met with an

accident. It is not denied by first party that, second party workman met with an accident while he was on duty. So I answer these issues to that effect.

#### Issue No.4.

17. Since second party died on 23-01-2007, question of considering his ability to perform duties after 23-01-2007 does not arise.

18. In view of discussions made above, I conclude that, reference of second party required to allow partly hence the order:

#### ORDER

- I. Reference is partly allowed.
2. Heirs of second party i.e. Smt. Pragati Prakash Dalvi, widow of deceased workman is entitled to get wages of deceased workman on the basis of his salary of that period from 17-08-1999 with all increments and hike in the salary till 23-01-2007 presuming that, deceased workman was in the employment of first party.
3. Other prayer of deceased workman to reinstate him or take his heir in the employment of first party or compassionate ground is turn down.
4. In the circumstances there is no order as to cost.

Date: 04-10-2007

A. A. LAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3502 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1 नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 119/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 20-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/98/2000-आई. आर.(बी-II)]  
राजेन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3502.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 119/2000) of Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Punjab National Bank, and their workmen, received by the Central Government on 20-11-2007.

[No. L-12012/98/2000-JR (B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE SHRI SANT SINGH BAL PRESIDING OFFICER

#### CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL No. I

NEW DELHI

I. D. No. 119/2000

In the matter of dispute between:

Shri Ajnesh,  
Through The General Secretary,  
P.N.B. Employees Union,  
W-8, Green Park,  
New Delhi - 16.

Workman

Versus

The Regional Manager,  
Punjab National Bank,  
Regional Office,  
Punjab National Bank,  
Atma Ram House,  
1, Tolstoy Marg,  
New Delhi.

Management

Appearances: None for the workman.

Shri Ashwani Sharma A/R for management.

#### AWARD

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/98/2000/IR(B-II) dated 18-10-2000 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of Punjab National Bank in not regularizing the services of Shri Ajnesh, Sweeper (Temporary/Part Time) is legal and just? If not, what relief is the said disputant, entitled to?”

2. After filing claim statement, written statement and rejoinder the case was fixed for filing document on 30-8-2004. Thereafter case was adjourned to 7-11-05 for filing documents and admission denial and many subsequent hearings on 18-1-06, 23-3-06, 5-6-06, 8-8-06, 1-11-06, 4-1-07, 1-3-07, 26-4-07, 19-6-07, 5-9-07, and today on 5-11-07 but none has been appearing for the workman since 26-4-07. The workman lastly appeared in this case on 1-3-07. It appears that the workman is not interested in the prosecution of his claim. Hence No Dispute Award is accordingly passed. File be consigned to record room.

DATED : 5-11-2007

SANT SINGH BAL, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3503 :**—ऑद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार व्यास प्रोजेक्ट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट ऑद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 73/91) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/177/90-आई. आर.(डी. यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3503.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 73/91) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Beas Project and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-42012/177/90-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT, No. I.  
CHANDIGARH**

Case No I.D. 73/91

Sh. Om Parkash	Applicant
S/o Sh. Amar Singh, Village Sandoli, P. O. Baddi, Tehsil Nalagarh, Distt. Solan (HP).	

Versus

The Chief Engineer, (Electrical) Beas Project, Sector 17-A, Chandigarh.	Respondent
---	------------

#### APPEARANCES

For the workman : Sh. Ramnik Gupta Advocate.  
For the management : Ms. Neeru Chadha.

#### AWARD

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-42012/177/90-IR (D.U.) dated 14-6-1991 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of the Chief Engineer (Electrical) Beas Project, Chandigarh in

terminating the services of Sh. Om Prakash, S/o Sh. Amar Singh w.e.f. 31-7-1985 is justified? If not, what relief is the workman concerned is entitled to?”

2. The case fixed for settlement for dispute between Om Parkash workman and management of Beas Project on 17-1-07. The management considered the request and came out today in settlement in Lok Adalat and submitted that management settled the dispute as prayed by the workman on 17-1-07 and brought a cheque of Rs. 75000/- in settlement which was acceptable to the workman on 17-1-07. Today son of the workman Om Parkash deceased came with his advocate and submitted that workman has expired on 30-3-07 leaving four survivor LR's Varinder Singh, Bal Krishan, Meena Kumari (children) and Kashmire Kaur wife and an application has been filed under Order 22 CPC on 24-10-07 for impleading the LRs. Copy given. The management has no objection as also it is an inter-se dispute between surviving LRs and an affidavit has been filed by Varinder Singh has been filed and special attorney on behalf of other three LRs (Death certificate filed). The management has no objection on bringing the LRs on record. LRs. submit that in view of the desire of their deceased father for settlement, they have also settled the dispute with the management and also agreed whatever the management is giving to them. They are ready to settle the dispute in Lok Adalat by accepting the cheque on behalf of their deceased father Om Parkash and they will distribute among LRs. this cheque. Hence matter may be decided as settled.

3. In view of the above dispute is returned as settled. Cheque No. B 228978 dated 16-10-07 for Rs. 75000/- drawn on S. B. I. Bhiwani is given to Varinder Singh son who is special attorney of all other three LR's against proper receipt. The matter is settled in Lok Adalat in above terms. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh

31-10-2007

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3504 :**—ऑद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार आर्मी स्कूल के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट ऑद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-14012/11/2005-आई. आर.(डी. यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3504.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2006) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Army School and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-14012/11/2005-IR(DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.**

Case No I.D. 25/2006

Smt. Surjit Kaur  
C/o Sh. M. R. Dhiman,  
Bhartiya Mazdoor Sangh,  
Puri Road, Arya Samaj,  
Patiala (Punjab).

Applicant

Versus

The Principal,  
Army School, 40, Baradari,  
Patiala (Punjab).

Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri. M. R. Dhiman.  
For the management : Shri. Rakesh Joshi.

#### AWARD

Passed on 31-10-2007

Central Government vide notification No. L-14012/11/2005IR (D.U.) dated 22-5-2006 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Army School, Patiala in terminating the services of Smt. Surjit Kaur, Ex-Sweepress w.e.f. 16-11-2004 without complying with the provisions of the ID Act, 1947 is legal and justified? If not, to what relief the concerned workman is entitled to and from which date?"

2. Case taken up in Lok Adalat at the request of the parties. Workman on 16-7-07 made the statement that she receives a cheque of Rs. 25000/- through a cheque No. 104212 dated 3-7-07 as full and final settlement of her claim including right of reinstatement, reemployment or my amount of the payment of gratuity etc. from M/s. Army School. She also stated that she forego her right of reinstatement or re-employment with the school management. I have no pending claim against the management and she shall not raise any kind of dispute to claim against the M/s. Army School Patiala. In view of her settlement, she withdraw her both the cases i.e. reference No. L-14012/11/2005/IR (DU) I.D. No. 25/06 in this court

and reference No. 605/05 at Labour Court Patiala and her cases may be dismissed as settled.

3. In view of the above statement and clearance of the cheque by the bank, the present reference is returned to the Central Govt. as settled. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3505 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947. (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण /श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 227/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/9/2000-आई. आर.(डी. यू.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3505.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 227/2000) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/9/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. I, CHANDIGARH.**

Case No I.D. 227/2000

Sh. Gurtej Singh  
S/o Sh. Piara Singh,  
C/o Sh. N. K. Jeet, President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001.

Applicant

Versus  
(a) The General Manager,  
Telecom, Bhatinda  
(Punjab)-151001.

Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
 For the management : Shri. G. C. Babbar.

**AWARD**

Passed on 31-10-2007.

Central Govt. vide notification No. L-40012/9/2000/IR (D.U.) dated 30-5-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :—

“Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating the services of Sh. Gurtej Singh S/o Sh. Piara Singh is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled and from which date ?”

The Case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3506 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण /श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 203/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[स. एल-40012/27/2000-आई. आर.(डी. यू.)]  
 सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3506.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 203/2000) Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/27/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO.-I, CHANDIGARH.**

Case No I.D. 203/2000

Sh. Kulvir Singh  
 C/o Sh. N. K. Jeet, President,  
 Telecom Labour Union,  
 Mohalla Hari Nagar,  
 Lal Singh Basti Road,  
 Bhatinda (Pb.)-151001.

Versus

(a) The General Manager,  
 Deptt. Of Telecom,  
 Hoshiarpur-146001.

**APPEARANCES**

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
 For the management : Ms. Deepali Puri.

**AWARD**

Passed on 31-10-2007.

Central Govt. vide notification No. L-40012/27/2000/IR (D.U.) dated 30-5-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Hoshiarpur (Pb.) in ordering disengagement/termination of services of Sh. Kulvir Singh a workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 1-3-99 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled and from which date ?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3507:—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण /श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या

209/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/72/2000-आई आर (डी. यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3507.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 209/2000) Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/72/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer  
**ANNEXURE**

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, -I,  
CHANDIGARH.

Case No I.D. 209/2000

Sh. Kamaljit Singh Sodhi, C/o Sh. N. K. Jeet, President, Telecom Labour Union, Mohalla Hari Nagar, Lal Singh Basti Road, Bhatinda (Pb.)-151001.	Applicant
--	-----------

Versus

(a) The General Manager, Dept. Of Telecom, Hoshiarpur-152001.	Respondent
---	------------

#### APPEARANCES

For the workman : For the management :	Shri. R. P. Singh. Ms. Deepali Puri.
---	---

#### AWARD

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/72/2000/IR (D.U.) dated 31-5-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Hoshiarpur (Pb.) in ordering disengagement/termination of services of Sh. Kamaljit Singh Sodhi a workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 1-3-99 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman

Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3508.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतांत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं.-I, चंडीगढ़ के पचाट (संदर्भ संख्या 61/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/495/2000-आई आर (डी. यू.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3508.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 61/2001) Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/495/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, -I,  
CHANDIGARH.

Case No I.D. 61/2001

Sh. Gurcharan Ram, C/o Sh. N. K. Jeet, 27349, Lal Singh Basti Road, Bhatinda (Pb.)-151001.	Applicant
---	-----------

Versus

(a) The General Manager, Dept. of Telecom, Hoshiarpur-146001.	Respondent
---	------------

#### APPEARANCES

For the workman : For the management :	Shri. R. P. Singh. Ms. Deepali Puri.
---	---

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/495/2000/IR (D.U.) dated 31-01-2001 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Hoshiarpur in ordering disengagement/termination of services of Sh. Gurcharan Ram workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 28-2-99 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date ?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

**RAJESH KUMAR**, Presiding Officer  
नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3509 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण /श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 53/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/484/2000-आई. आर.(डी. यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3509.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 53/2001) Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/484/2000-IR (DU)]  
**SURENDRA SINGH**, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,  
CHANDIGARH**

Case No I.D. 53/2001

Sh. N. K. Jeet, President,  
Telecom Labour Union,  
27349,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)

Applicant

**Versus**

(a) The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Hoshiarpur.

Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
For the management : Ms. Deepali Puri.

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/484/2000/IR (D.U.) dated 29-12-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Hoshiarpur in ordering disengagement/termination of services of Sh. Hardip Singh a workman engaged through contractor M/s Ram Krishan Budhram w.e.f. 28-2-2000 is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled and from which date ?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07 **RAJESH KUMAR**, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3510 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण /श्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 43/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/450/2000-आई. आर.(डी. यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3510.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 43/2001) Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their

workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/450/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,-I, CHANDIGARH.

Case No I.D. 43/2001

Sh. N. K. Jeet, President,  
Telecom Labour Union,  
27349,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

Applicant

Versus

(a) The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Hoshiarpur-146001.

Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
For the management : Ms. Deepali Puri.

#### AWARD

Passed on 31-10-2007.

Central Govt. vide notification No. L-40012/450/2000/IR (D.U.) dated 18-01-2001 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether action of the management of General Manager, Telecom, Hoshiarpur (Pb). in ordering disengagement/termination of services of Sh. Manjit Singh a workman engaged through contractor M/s Gurbachan Lal w.e.f. 28-2-99 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3511.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर

संचार विभाग के प्रबंधालय के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण /अम. न्यायालय नं.-I, चंडीगढ़ के पंजाट (संदर्भ संख्या 221/2000) को प्रकाशित करती है, कि केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था :

[सं. एस-40012/23/2000-सर. अध. (डी. प.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क ऑफिसर

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3511.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 221/2000) Central Government Industrial Tribunal cum Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/23/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

#### BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT,-I, CHANDIGARH.

Case No I.D. 221/2000

Sh. Amrik Singh C/o Sh.N.K.Jeet,  
President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

Applicant

Versus  
(a) The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Hoshiarpur-152001. (Punjab)

Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
For the management : Ms. Deepali Puri.

#### AWARD

Passed on 31-10-2007.

Central Govt. vide notification No. L-40012/23/2000/IR (D.U.) dated 30-05-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the General Manager, Telecom, Hoshiarpur (Pb). in ordering disengagement/termination of services of Sh. Amrik

Singh a workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 1-3-99 is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from which date ?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3512.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/प्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 185/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/17/2000-आई आर (डी. यू.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3512.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 185/2000) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. I, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/17/2000-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL- CUM-LABOUR COURT NO. I,  
CHANDIGARH

Case No I. D. 185/2000

Sh. Prakash Singh C/o Sh. N.K. Jeet,  
President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

Applicant

#### Versus

The General Manager,  
Telecom,  
Bhatinda-152001. (Punjab) 151001

Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri. R. P. Singh.

For the management : Shri G.C. Babbar.

#### AWARD

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/17/2000/IR (D.U.) dated 30-05-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating services of Sh. Prakash Singh S/o. Sh. Harbans Singh is legal and justified ? If not, to what relief the workman is entitled and from which date ?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3513.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/प्रम न्यायालय नं.-I, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 139/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/41/2002-आई आर (डी. यू.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3513.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 139/2002) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. I, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/41/2002-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

## ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1,  
CHANDIGARH.**

Case No I.D. 139/2002

Sh. Jaswant Singh C/o./ N. K. Jeet  
H.No. 27349,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151005

Applicant

Versus

The General Manager,  
Dept. Of Telecom,  
Amritsar (Punjab)

Respondent

## APPEARANCES

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
For the management : Shri G.C.Babbar.

## AWARD

Passed on 31-10-2007.

Central Govt. vide notification No. L-40012/41/2002/IR (D.U.) dated 24-7-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Amritsar in terminating the services of Sh. Jaswant Singh S/o. Sh. Gurnam Singh workman w.e.f. 28-2-99 is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date ?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.  
31-10-07

**RAJESH KUMAR, Presiding Officer**

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3514 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धात्र 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचार विभाग के प्रबंधतान्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्णिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण / श्रम न्यायालय नं.-I, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 137/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/60/2002-आई. आर. (डी. यू.)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007.

S.O. 3514.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 137/2002) Central Government Industrial-Tribunal-cum-Labour Court, No. I, Chandigarh as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/60/2002-IR (DU)]

**SURENDRA SINGH, Desk Officer**

## ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, NO. 1,  
CHANDIGARH**

Case No I.D. 137/2002

Sh. Bikram Singh C/o. Sh. N. K. Jeet.

H. No. 27349,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)

Applicant

Versus

The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Amritsar (Punjab)

Respondent

## APPEARANCES

For the workman : Shri. R. P. Singh.  
For the management : Shri G.C.Babbar.

## AWARD

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/60/2002/IR (D.U.) dated 24-7-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Amritsar in terminating the services of Sh. Bikram Singh S/o. Sh. Tarlok Singh workman w.e.f. 28-2-99 is just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date ?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh.

31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3515:**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 29/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/186/2002-आई आर(डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3515.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 29/2003) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/186/2002-IR(DU)]  
SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH**  
Case No I. D 29/2003

Sh. Baljeet Singh,  
C/o. Sh N.K. Jeet, 27349  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

...Applicant

#### VERSUS

The General Manager,  
Telecom, BSNL E-10B Building  
Behind HPO, Bhatinda (Punjab)

...Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri R.P. Singh  
For the management : Shri G.C. Babbar

#### AWARD

Passed on 31-10-07

Central Govt. vide notification No. L-40012/186/2002-IR (DU) dated 18-02-2003 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom; (BSNL) Bhatinda in terminating the services of Sh. Baljeet Singh S/o Sh. Balram Singh workman, w.e.f. 1-3-99 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh

31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3516 :**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 59/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/330/2001-आई आर(डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3516 .**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 59/2002) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/330/2001-IR(DU)]  
SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH**  
Case No I.D 59/2002

Sh. Nand Lal,  
C/o. Sh N.K. Jeet, 27349, Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151001

... Applicant

#### VERSUS

The Telecom District Manager,  
BSNL  
Ropar-140001

... Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri R.P. Singh  
For the management : Ms. Deepali Puri

**AWARD**

Passed on 31-10-07.

Central Govt. vide notification No. L-40012/330/2001-IR (DU) dated 14-03-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Telecom Distt. Manager, BSNL, Ropar in terminating the services of Sh. Nand Lal S/o Sh. Budh Ram workman, w.e.f. 1-03-99 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

**Chandigarh** RAJESH KUMAR, Presiding Officer  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3517 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 57/2002) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/336/2001-आई आर(डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3517.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 57/2002) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/336/2001-IR (DU)]  
SURENDRA SINGH, Desk Officer  
**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,  
CHANDIGARH**  
Case No I. D 57/2002

Sh. Jaswant Singh,  
C/o. Sh N.K. Jeet, H. No. 27349,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151005

...Applicant

**VERSUS**

The Telecom District Manager,  
BSNL  
Ropar-140001

...Respondent

**APPEARANCES**

For the workman: Shri : R.P. Singh  
For the management : Ms. Deepali Puri

**AWARD**

Passed on 31-10-07

Central Govt. vide notification No. L-40012/336/2001-IR (DU) dated 14-03-2002 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Telecom Distt. Manager, BSNL, Ropar terminating the services of Sh. Jaswant Singh S/o Sh. Gurbak Singh workman, w.e.f. 1-03-99 is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

**Chandigarh** RAJESH KUMAR, Presiding Officer  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3518 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं-1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 333/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/238/2001-आई आर (डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3518.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 333/2001) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/238/2001-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH**  
**Case I. D. No. 333/2001**

Sh. Ashok Kumar,  
C/o. Sh N.K. Jeet,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

...Applicant

**Versus**

The General Manager,  
Telecom,  
Bhatinda (Pb.)-151001.

Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri R.P. Singh  
For the management : Shri G.C. Babbar

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/238/2001-IR (DU) dated 06-11-2001 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating the services of Sh. Ashok Kumar S/o Sh. Sohan Lal is just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh                    RAJESH KUMAR, Presiding Officer  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3519.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 175/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/478/99-आई आर (डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3519.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 175/2000) of Central Government Industrial Tribunal-cum-

Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/478/99-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBU-  
NAL CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH**

**Case I. D No. 175/2000**

Sh. Raj Singh S/o Bir Singh,  
C/o. Sh N.K. Jeet,  
President, Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

...Applicant

**Versus**

The General Manager,  
Telecom,  
Bhatinda (Pb.)-151001.

Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri R.P. Singh  
For the management : Shri G.C. Babbar

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/478/99-IR (DU) dated 13-03-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating the services of Sh. Raj Singh S/o Sh. Bir Singh is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh                    RAJESH KUMAR, Presiding Officer  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3520.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ

संख्या 177/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/474/99-आई. आर.(डी.यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3520**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 177/2000) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/474/99-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH

Case I.D. No. 177/2000

Sh. Beant Singh S/o Gurdev Singh,  
C/o. Sh N.K. Jeet,  
President, Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

Applicant

#### VERSUS

The General Manager,  
Telecom,  
Bhatinda (Pb.)-151001.

Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri R.P. Singh  
For the management : Shri G.C. Babbar

#### AWARD

Passed on 31-10-07

Central Govt. vide notification No. L-40012/474/99-IR (DU) dated 13-03-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating the services of Sh. Beant Singh S/o Sh. Gurdev Singh is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman

Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh  
31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3521**.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतांत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/प्रम न्यायालय नं. 1, चंडीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 159/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/460/99-आई. आर.(डी.यू.)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3521**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 159/2000) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/460/99-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH

Case I.D No. 159/2000

Sh. Gurcbaran Singh  
C/o. Sh N.K. Jeet,  
President, Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151001

...Applicant

#### Versus

The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Hoshiarpur 146001.

...Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri R. P. Singh  
For the management : Ms. Deepali Puri.

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/460/99-IR (DU) dated 13-03-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the General Manager, Telecom, Hoshiarpur in ordering disengagement/termination of services of Sh. Gurcharan Singh, workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 1-3-99 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3522.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 219/99) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/175/99-आई आर(डी यू)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3522.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 219/99) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. I Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/175/99-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer  
ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-I,  
CHANDIGARH**

Case No. I.D. 219/99

Miss Neetu  
C/o. The President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151001

...Applicant

**Versus**

The General Manager,  
Telecom,  
Bhatinda (Pb.)-151001.

... Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri R. P. Singh  
For the management : Shri G. C. Babbar

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/175/99-IR (DU) dated 29-09-1999 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether action of the management of the General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating the services of Ms. Neetu just and legal? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?"

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh  
31-10-07

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3523.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 165/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/462/99-आई आर(डी यू)]

सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3523.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 165/2000) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. I, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/462/99-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer

**ANNEXURE**  
**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH**  
**Case No. I.D. 165/2000**

Miss Anju Bala  
C/o. Sh. N.K. Jeet  
President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151001

... Applicant  
Versus

The General Manager,  
Dept of Telecom,  
Hoshiyarpur-146001.

... Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri R.P. Singh  
For the management : Ms. Deepali Puri

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/462/99-IR (DU) dated 13-03-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether the action of the General Manager, Telecom, Hoshiyarpur (Pb.) in ordering disengagement/termination of services of Miss. Anju Bala workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 1-3-99 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3524.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं. 1, चण्डीगढ़ के पांचाट (संदर्भ संख्या 163/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/464/99-आई आर(डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेरक अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3524.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central

Government hereby publishes the Award (Ref. No. 163/2000) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workman, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/464/99-IR (DU)]

SURENDRA SINGH, Desk Officer  
ANNEXURE

**BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,  
CHANDIGARH**

Case No. I. D. 163/2000

Ms. Kulwinder Kaur  
C/o. Sh. N.K. Jeet  
President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151001

... Applicant

Versus

The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Hoshiyarpur-146001.

... Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri R. P. Singh  
For the management : Ms. Deepali Puri

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/464/99-IR (DU) dated 13-03-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of the General Manager, Telecom, Hoshiyarpur (Pb.) in ordering disengagement/termination of services of Miss. Kulwinder Kaur workman engaged through contractor Sh. Ashok Kumar Sharma w.e.f. 1-3-99 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to and from which date?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh                    RAJESH KUMAR, Presiding Officer  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3525.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार दूर संचार

विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 41/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/448/2000-आई आर (डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3525**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 41/2001) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/448/2000-IR (DU)]  
SURENDRA SINGH, Desk Officer  
ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH  
Case No I. D. 41/2001

Sh. N. K. Jeet,  
President,  
Telecom Labour Union,  
27349,  
Lal Singh Basti Road,  
Bhatinda (Pb.)-151001

....Applicant  
Versus

The General Manager,  
Dept. of Telecom,  
Hoshiarpur-146001.

....Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri R. P. Singh  
For the management : Ms. Deepali Puri

**AWARD**  
Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-40012/448/2000-IR (DU) dated 18-01-2001 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

“Whether action of the Management of the General Manager, Telecom, Hoshiarpur (Pb.) in ordering disengagement/termination of services of Sh. Raj Kumar a workman engaged through contractor M/s. Gurbachan Lal w.e.f. 25-4-98 just and legal ? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?”

2. The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok

Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3526** :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार द्वारा संचार विभाग के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 223/2000) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-40012/14/2000-आई आर(डी यू)]  
सुरेन्द्र सिंह, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3526**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 223/2000) Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of Department of Telecom and their workmen, which was received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-40012/14/2000-IR (DU)]  
SURENDRA SINGH, Desk Officer  
ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING  
OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL  
TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,  
CHANDIGARH

Case No. I. D. 223/2000

Sh. Jagsir Singh  
S/o Sh. Piara Singh  
C/o Sh. N. K. Jeet,  
President,  
Telecom Labour Union,  
Mohalla Hari Nagar,  
Lal Singh Basti Road, Bhatinda  
(Pb.)-151001

...Applicant

#### VERSUS

The General Manager,  
Telecom,  
Bhatinda (Punjab)-151001.

...Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri R. P. Singh  
For the management : Shri G. C. Babbar

#### AWARD

Passed on 31-10-07

Central Govt. vide notification No. L-40012/14/2000-IR (D.U.) dated 29-05-2000 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of the General Manager, Telecom, Bhatinda in terminating the services of Sh. Jagsir Singh &/o Sh. Piara Singh is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled and from which date?"

The case is taken up in Lok Adalat at the request of the parties. The authorized representative of the workman Shri Ram Partap Singh withdraw the present reference vide his statement recorded on 31-10-2007. In view of the same, the present reference is returned as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

Chandigarh                    RAJESH KUMAR, Presiding Officer  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3527.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार सी. पी. डब्ल्यू. डी. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 283/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/304/2003-आई. आर.(सीएम-II)]  
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3527.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 283/2004) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Central Public Work Department and their workmen, received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-42012/304/2003-IR (CM-II)]  
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

#### ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT, -1,  
CHANDIGARH

Case No I. D. 283/2004

The Zonal Secretary,  
All India CPWD (MRM)  
Karamchari Sangathan,  
CPWD. Store Building,  
Sector 7-B, Chandigarh.

Applicant

#### Versus

The Executive Engineer,  
Central Public Work Department,  
Chandigarh Central Electrical Division,  
Kendriya Sadan, Sector 9-A, Chandigarh

Respondent

#### APPEARANCES

For the workman : Shri Raj Kumar  
For the management : Shri G. C. Babbar.

#### AWARD

Passed on 31-10-07

Central Govt. vide notification No. L-42012/304/2003-IR (C M II) dated 23-08-2004 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the contract between the management of CPWD and their contract is sham and the demand of All India CPWD (MRM) Karamchari Sangathan for regularization of the services of Shri Anil Kumar Kalra in the Organization of CPWD is legal and justified? if not, to what relief they are entitled?

2. Case taken up in Lok Adalat at the request of the AR of the Union Shri Raj Kumar Zonal Present All India CPWD (MRAM) Karamchari Sangathan, Chandigarh made a statement that the Union in this case is not interested to pursue with the matter further and withdraw the same in Lok Adalat today.

3. In view of the statement of the AR of the workman that Union in this is not interested to pursue with the matter further and withdraw the same in Lok Adalat today, the present reference is returned to the Central Govt. as withdrawn in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3528 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बी.बी.एम.बी के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 129/2k) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-23012/2/1999-आई. आर.(सी-II)]  
अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3528.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 129/2k) of the Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court, No. 1 Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the employers in relation to the management of BBMB and their workmen, which was received by the Central Government on 26-II-2007.

[No. L-23012/2/1999-IR (C-II)]  
AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer  
ANNEXURE

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1,  
CHANDIGARH

Case No I. D. 129/2000

Sh. Ram Nath  
C/o Sh. R.K. Singh,  
Secy., Punjab INTUC,  
35-G, Nangal Township.

... Applicant

**Versus**

The Chief Engineer,  
Bhakra Dam,  
Nangal Township,  
Distt. Roper (Punjab).

... Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri R.K. Singh.  
For the management : Shri Rajinder Singh.

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-23012/2/99-IR (CM-II) dated 29-2-1999 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication :

"Whether the action of the management of BBMB, Nangal Township, Distt. Ropar in terminating the services of Sh. Ram Nath S/o Sh. Ram Chand is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled?"

2. Case taken up in Lok Adalat today. AR of the workman shri R.K. Singh made a statement that the matter has been settled amicably and the workman does not want to pursue with the present reference. The same may be returned as settled in Lok Adalat.

3. In view of the above statement of the recorded today the present reference is returned as settled. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh  
31-10-2007

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3529.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार स्माल इन्डस्ट्रीज सरवीस इन्स्टीट्यूट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण नं-1, चण्डीगढ़ के पंचाट (संदर्भ संख्या 15/2003) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।**

[सं. एल-42012/185/2001-आई आर (सी एम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3529.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 15/2003) of the Central Government Industrial Tribunal-**

cum-Labour Court No. 1, Chandigarh as shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the management of Small Industries Service Institute and their workmen, received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-42012/185/2001-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer

**ANNEXURE**

BEFORE SHRI RAJESH KUMAR, PRESIDING OFFICER, CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT-1, CHANDIGARH

Case No I.D 15/2003

Sh. Balikaran Prasad  
C/o Sh. B.N. Sehgal  
49/69, Harpal Nagar, Ludhiana.

... Applicant

**Versus**

The Director,  
Small Industries Service Institute,  
Industrial Area-B,  
Ludhiana-141003

... Respondent

**APPEARANCES**

For the workman : Shri B.N. Sehgal  
For the management : Shri K.K. Thakur

**AWARD**

Passed on 31-10-2007

Central Govt. vide notification No. L-42012/185/2001-IR (C-II) dated 14-1-2003 has referred the following dispute to this Tribunal for adjudication:

"Whether the action of the management of Small Industries Service Institute, Ludhiana in terminating Sh. Balikaran Parshad from services is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to?"

2. Case taken up in Lok Adalat today. AR of the workman shri B.N. Sehgal made a statement on 29-10-07 that on instructions from workman Bali Karan Prashad that matter has been settled and workman has been reinstated and he has joined his duties and this case may be disposed off as settled in Lok Adalat as learned court made efforts in this regard.

3. In view of the statement of the advocate of the workman Shri B.N. Sehgal, the present reference is withdrawn and returned as settled in Lok Adalat. Central Govt. be informed. File be consigned to record.

RAJESH KUMAR, Presiding Officer

Chandigarh  
31-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3530.—**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार नेशनल फर्टीलाइजर कॉम्प्लिटी एण्ड ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण नं. 2, नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 81/2006) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 26-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-42012/178/2005-आई आर (सीएम-II)]

अजय कुमार गौड़, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3530.—**In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 81/2006) of Central Government Industrial Tribunal-cum-Labour Court No. 2, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Central Fertilizer Quality Control and Training Institute, and their workmen, received by the Central Government on 26-11-2007.

[No. L-42012/178/2005-IR (CM-II)]

AJAY KUMAR GAUR, Desk Officer  
ANNEXURE

**BEFORE THE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT - II, NEW DELHI**

Presiding Officer : R. N. RAI.

I.D. No. 81/2006

In the matter of:

Shri Jagbir Singh,

S/o. Shri Tej Ram, Village: Bhankri,

Tehsil & Distt: Faridabad, Post: Pali,

Faridabad (Haryana).

**VERSUS**

The Director,

Central Fertilizer Quality Control & Training Institute,  
NH - IV, Faridabad (Haryana).

**AWARD**

The Ministry of Labour by its letter No. L-42012/178/2005-IR (CM-II) Central Government 17-10-2006 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

“Whether the action of the management of Central Fertilizer Quality Control & Training Institute in terminating the services of Shri Jagbir Singh, S/o. Shri Tej Ram, Chowkidar/

Security Guard w.e.f. 02-09-2004 is legal and justified? If not, to what relief the workman is entitled to.”

The workman applicant has filed claim statement. In the claim statement it has been stated that the claimant/ workman was called for interview for the post of Chowkidar by the respondent vide letter dated 16-10-2003 and was appointed as Chowkidar/Security Guard on daily wages basis by the respondent vide letter dated 28-10-2003.

That the workman worked regularly from 28-10-2003 to 02-09-2004 as daily wager Security Guard and has completed more than 240 days during his service.

That on 02-09-2004, the respondent terminated the services of the workman absolutely in an illegal and arbitrary manner without complying with the mandatory provisions of the ID Act, 1947 and against the principles of natural justice.

That during his service span from 28-10-2003 to 02-09-2004 the workman regularly worked as a Chowkidar / Security Guard and was duly paid by the respondent.

That the unfair labour practice is at the peak in the respondent Office. The respondent appoints any person at any time and terminates any employee at any time in flagrant violation of the laws of the country. The services of the workman have also been terminated by the respondent in the same manner, which amounts to an instance of grave unfair labour practice of which the workman is a victim.

That the termination of the services of the workman by the respondent on 02-09-2004 is absolutely illegal, null and void ab initio against the provisions of the Constitution of India and is non-existent in the eyes of law and is liable to be set aside on the grounds of inter alia the following :

That no notice or pay in lieu of notice and retrenchment compensation was paid to the workman at the time of termination of his services which is in violation of Section 25 F/25 N of the ID Act, 1947.

That no permission was sought from the appropriate Government by the respondent before terminating the services of the workman as required under Section 25 N of the ID Act, 1947.

That fresh person Mr. Virender, S/o. Smt. Kamla, Peon in the respondent department has been employed by the respondent in place of the workman after terminating the services of the workman which is in violation of the Section 25 H of the ID Act, 1947.

The management has filed reply to the claim statement. In the reply it has stated that Sh. Jagbir Singh joined his services on casual daily wages basis w.e.f. 28.10.2003. His dedication towards his duties and his attitude/behaviour towards his seniors was un-satisfactory since his joining. Moreover many a times the management

had received many complaints against the workman and perusing to which he was warned accordingly. Moreover many a times he was found in drunken state over which also he was warned by the management which remained without results. On 02-09-2004 he was again found in drunken state while he was on his duty and he also misbehaved with the other security guards on duty including an officer of the Institute. For his that misbehaviour he was again officially warned but realizing his guilt on his own he absented from duty after 02-09-2004.

It is submitted that Sh. Jagbir Singh had been deployed as Security Guard w.e.f. 28-10-2003 on purely casual and daily wages basis as per the rate prescribed by Dy. Commissioner, Faridabad for daily wages after being sponsored by Zila Sainik Board, Faridabad. He was not appointed on any post of permanent nature. He was well informed that his services are only on casual daily wages basis as per the rate fixed by the Haryana Government.

It is submitted that the applicant was taken by the Institute on purely daily wages as per need basis. It is not correct that he has regularly worked for more than 240 days without break. The fact is that he has worked only for 25 days to maximum 29 days in a month with the break varying from 2 to 5 days in different months. Thus, there is no continuous working on daily wages basis. The applicant was paid only for the day for which he worked.

It is submitted that he was found in drunken state on 02-09-2004 while on duty and misbehaved with other security guard and even the officer of the institute. This was an unpardonable misbehaviour, disobedience and also liability for the institute. Further realizing his guilt on his own he absented from duty after 02-09-2004.

That since his working was not found satisfactory and he indulged into misconduct and dereliction of duty, of coming on duty in drunken state and quarrelling with fellow colleagues, risking the safety and security of the laboratory and its belongings and further not mending his habits even after verbal and written warnings, he was removed.

That as already stated above realizing his serious misconduct the workman absented himself at his own w.e.f. 02-09-2004.

That the institute is a Central Government Office engaged in the General Development activities and it is not an industrial organization and not engaged in any production work and so not an "Industry" and hence the Industrial Dispute Act does not apply herein. Further the Section 25 F of the Act is not applicable because the workman was deployed as daily wager in Government Office on casual work. Also his deployment was only on need based daily wages basis, there is no termination of service in this case; there is no illegality and arbitrariness.

That the claimant was given appropriate opportunity

to improve himself. He was verbally warned on 03-06-2004 for attending duty in drunken state and quarrelling with other security guards. He had apologized for the same for his misbehaviour and promised not to drink during duty hours. Even then there was no improvement.

The applicant was deployed only on daily wages basis.

The workman applicant has filed rejoinder. In the rejoinder he has reiterated the averments of his claim statement and has denied most of the paras of the written statement. The management has also denied most of the paras of the claim statement.

Evidence of both the parties has been taken.

Heard argument from both the sides and perused the papers on the record.

It was submitted from the side of the workman that the institute is a Central Government Office engaged in the General Development activities and it is not an industrial organization and not engaged in any production work and so not an "Industry" and hence the Industrial Dispute Act does not apply herein.

The management is engaged in systematic activities. It is engaged in general development activities. There is employer-employee relationship. It has been held in Bangalore Water Supply that in case where there is systematic activities, there is employer-employee relationship, the undertaking is an industry u/s 2 (j) of the ID Act, 1947. It is not denied that there is no systematic activities and there is no employer-employee relationship, so the management is an industry.

It was submitted from the side of the workman that he was appointed as casual labour on daily wages basis on 28-10-2003 and his services were terminated on 02-09-2004. He has completed more than 240 days. The management has not complied with the provisions of Section 25 F of the ID Act, 1947. He has not been paid retrenchment compensation and one month's pay in lieu of notice. Muster Roll register has been filed.

It becomes quite obvious from perusal of the muster roll that the workman has worked for more than 240 days in between 28-10-2003 to 02-09-2004. It is also admitted that the workman has not been paid retrenchment compensation and one month's pay in lieu of notice.

It was further submitted from the side of the workman that the management has alleged misconduct and drunkenness against the workman but he has not been served any charge sheet and no proper inquiry has been held.

It was submitted from the side of the management that the management received many complaints against the workman at many times and he was warned orally. He was found in drunken state on 02-09-2004, so he was asked

not to come. He also misbehaved with the other security personnel including Officer of the Institute for that he was again officially warned and realizing his guilt on his own, he absented himself from duty. The management has filed MW2 complaint by Security Personnel, Sh. Ishwar Singh. Ex. MW2 is the complaint against the workman Shri Jagbir Singh.

It is true that the name of the workman has not been mentioned in the complaint. It has been alleged in the complaint that when the other Security Personnel Shri Ishwar Singh came on 23:30, he knocked the main gate but none opened it. After jumping over the boundary he went inside and found that the workman was taking drinks in the Driver's room. An empty bottle of wine was also found there. The workman quarreled with him on 01-06-2004, 02-06-2004 and torned his shirt and he went away from duty at 00:30 and came at 00:55.

In this letter the name of the workman has not been mentioned. The incident relates to 01-06-2004 and 02-06-2004. On 01-06-2004 and 02-06-2004 Sh. Jagbir Singh and Sh. Ishwar Singh were on duty. The management has engaged two persons for alternate duty. When Sh. Ishwar Singh came Sh. Rajbir Singh was inside the premises.

The management has examined two witnesses Sh. Shalender Singh and Sh. Ishwar Singh. Shri Ishwar Singh is the complainant and he has proved Ex. MW2 which is written in his own handwriting and he has taken the name of workman who quarreled with him and torn his clothes, so from the evidence of Sh. Ishwar Singh, co-employee and Sh. Shailender Singh it is found proved that the workman was in drunken state on 12-06-2004.

It was submitted from the side of the workman that a stigma has been cast against the workman. No inquiry has been held by the management. The services of the workman has been arbitrarily terminated without serving chargesheet on him and holding appropriate inquiry.

A full-fledged inquiry is not necessary in every misconduct of a casual/ daily wager. In case the management is compelled to hold inquiry in every case of casual/ daily wagers, the management will go on holding inquiries. The workman was appointed as daily wager casual Chowkidar on 28-10-2003. Evidence of the management witness shows that the workman was in a habit of drinking inside the premises during the duty hours and this fact has been corroborated by two witnesses of the management. Sh. Ishwar Singh has been examined as MW2 and he has written complaint to the Director regarding drunkenness and misconduct of the workman. The workman was found again in drunken state on 02-09-2004 and he was asked not to come on duty. There is no mention of misconduct in termination order which can be held to be stigmatic.

My attention was drawn to 2007 LLR 1099. In this case the workman has worked for 7 years and there is a simple complaint of misbehaviour with a student. There is

no such allegation of drunkenness while on duty and fighting with other co-employees. The management has taken the case that he was found in drunken state on several occasions and he was warned orally. Sh. Ishwar Singh, the co-employee made a complaint and the matter was inquired into and on 02-09-2004 the workman was again found in a drunken state.

It becomes quite obvious from the above that fullfledged inquiry is not necessary in every case on a misconduct of a casual employee who has worked for a short period. The management found sufficient proof of misconduct and that is why the management asked the workman not to come on duty. There is sufficient evidence in the record to establish that the workman used to take alcohol while on duty.

In the circumstances narrated above provisions of Section 25 F of the ID Act, 1947 are not attracted and detailed inquiry is not required in every case. There was complaint of drunkenness by co-security personnel. Under the circumstances the management has rightly stopped the workman on 03-09-2004 from resuming his duties. In cases where a workman has worked for sufficient duration he has obtained almost a right to service and in those cases inquiry is necessary as has been held in 2007 LLR 1099. In the instant case the workman has hardly worked for a year and he was found in a drunken state on several occasions. The management cannot be compelled to reinstate such workman or even to pay compensation in view of grave misconduct committed by the workman.

The reference is replied thus:

The action of the management of Central Fertilizer Quality Control & Training Institute in terminating the services of Shri Jagbir Singh, S/o. Shri Tej Ram, Chowkidar Security Guard w.e.f. 02-09-2004 is legal and justified. The workman applicant is not entitled to get any relief as prayed for.

The award is given accordingly.

Date: 20-11-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3531.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार औरिएंटल इंशोरेन्स कं. लि. के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्देश औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय जबलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 181/97) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-17012/32/1996-आई. आर.(बी-II)]

राजित कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3531**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. 181/97) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Oriental Insurance Co. Ltd. and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-17012/32/1996-IR(B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS-  
TRIAL**

**TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,  
JABALPUR**

**NO. CGIT/LC/R/181/97**

**PRESIDING OFFICER: SHRI C.M.SINGH**

Shri Shivdas Jharia,  
Purani Basti, Azad Nagar,  
Ranjhi,

Jabalpur (MP)

Workman/Union

Versus

Divisional Manager,  
Oriental Insurance Co.Ltd.,  
123, Napier Town,

Jabalpur(MP)

Management

**AWARD**

Passed on this 29th day of October-2007

1. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-17012/32/96/IR(B-II) dated 30-5-97/7-797 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:

“Whether the action of the management of Oriental Insurance Co.Ltd., Jabalpur in terminating the services of Sh.Shivdas Jharia, Development Officer vide their order dated 21-7-94 is legal and justified? If not, to what relief the said workman is entitled?”

2. Order dated 26-10-07 passed on the order-sheet of this reference proceeding reveals that inspite of sufficient service of notice, the parties did not turn up and no body put in appearance for them.

3. Under the above circumstances, this tribunal was left with no option but to close the reference for award.

4. It is a no evidence case. Therefore it deserves to be decided against the workman and in favour of the management without any orders as to cost. The reference is decided in favour of the management and against the workman without any orders as to

costs holding that the action of the management of Oriental Insurance Co.Ltd., Jabalpur in terminating the services of Sh.Shivdas Jharia, Development Officer vide their order dated 21-7-94 is legal and justified and consequently the workman is not entitled to any relief.

5. Let the copies of award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3532.**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतात्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय जवलपुर के पंचाट (संदर्भ संख्या 53/2004) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/13/2004-आई. आर.(बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3532**.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 53/2004) of Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court Jabalpur as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Bank of India and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-12011/13/2004-IR(B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUS-  
TRIAL**

**TRIBUNAL CUM LABOUR COURT,  
JABALPUR**

**NO. CGIT/LC/R/53/04**

**PRESIDING OFFICER: SHRI C.M. SINGH**

The General Secretary,  
Union Bank of India,  
Ashirvad Market, Lordganj,  
Jabalpur

Workman/Union

Versus

The Zonal Manager,  
Bank of India,  
Zonal Office, Govind Kunk Colony, Russel Chowk,  
Jabalpur.  
Management

**A WARD**

Passed on this 2nd day of November-2007

- I. The Government of India, Ministry of Labour vide its Notification No.L-12011/13/2004-IR(B-II) dated 2-6-2004 has referred the following dispute for adjudication by this tribunal:-

“Whether the action of the management of Bank of India is not giving promotional financial benefit to Sh.K.K.Donge then Cash Clerk, Khamaria Branch is justified? If not, what relief is the concerned workman entitled to?”

2. Order dated 1-11-07 passed on the ordersheet of this reference reveals that the workman/Union did not file any statement of claim and prayed for closing the reference as the dispute appears to have been settled between the parties. That the counsel for the management did not object for closing the reference. That, therefore the reference was closed for award.
3. It is a case without any pleadings and without any evidence of the parties. The reference, therefore, deserves to be decided against the workman/Union and in favour of the management without any orders as to costs.
4. The reference is decided in favour of the management and against the workman without any orders as to costs holding that the action of the management of Bank of India in not giving promotional financial benefit to Sh.K.K.Donge the then Cash Clerk, Khamaria Branch is justified and consequently the concerned workman is not entitled to any relief.
5. Let the copies of the award be sent to the Government of India, Ministry of Labour & Employment as per rules.

C. M. SINGH, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3533 :—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धांगा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम व्यायालय नई दिल्ली के पंचाट (संदर्भ संख्या 27/2001) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12012/135/2000-आई. आर.(बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3533.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 27/2001) of Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court

No. 1, New Delhi as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Punjab National Bank and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-12012/135/2000-IR(B-II)]

**RAJINDER KUMAR**, Desk Officer  
**ANNEXURE**

**BEFORE SHRI SANT SINGH BAL PRESIDING OFFICER**

**CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL TRIBUNAL NO.1**

**NEW DELHI**

**I.D. NO. 27/2001**

In the matter of dispute between:

Shri Janak Raj Prashar,  
As represented by his L.Rs.  
Mrs. Chitra Parashar,  
Miss Meenakshi Parashar,  
Ms. Seema Parashar Kanika Parashar

Master Kuldeep

House No.2, Ward No.10,  
Mohalla Barh.,  
Old Faridabad .

L.Rs. of workman

Versus

Canara Bank,  
Through, Dv. General Manager,  
Canara Bank, Staff Circle Office,  
81-83, Sector -34 A,  
Plot No.1,  
Chandigarh-1600 17.

Management

Appearances: Workman in person.

Shri Rajat Arora A/R for the management,

**AWARD**

The Central Government in the Ministry of Labour vide its Order No.L-12042/135/2000/IR(B-II) dated 21-3-2001 has referred the following industrial dispute to this Tribunal for adjudication :

“Whether the action of the management of Canara Bank in compulsory retiring from service to Shri Janak Raj is justified and legal? If not, what relief the workman is entitled to?”

2. Brief facts of this case as culled from record are that the deceased workman Shri Janak Raj joined as clerk on 17.8.78 in the erstwhile Lakshmi Commercial Bank which was merged with Canara Bank in 1985 and continued to work in the clerical cadre and lastly he worked at Faridabad Branch. The workman was an active Trade Union Member of Haryana Bank Employees Federation and was holding the post of Joint Secretary in the Federation in the year 1998. His participation in union activities was not liked by the management and he was suspended for his union

activities and he was charge sheeted vide charge sheet dated 9-7-98 for having committed gross misconduct within the meaning of Chapter XI Regulation 3(k) of Canara Bank Service Code for assaulting, abusing and threatening and manhandling Mr. Katlaria Bank Manager in his cabin and giving fist blows on his face resulting 'injuries to his lips and teeth and causing bleeding. This act was prejudicial to the interest of the bank. Enquiry was held. The workman initially attended the inquiry but was proceeded ex parte. Five witnesses namely Shri S.K.Malik, Officer Tikona Park, Faridabad, Shri Satpal Marwah, Manager, Currency Chest, Faridabad, Shri Y.L.Madan, AGM, RO, Karnal, Shri M.S.Katlaria, Manager, Currency Chest Faridabad since working at A/c Section, Chandigarh, Shri I.N.Sharma, Chief Manager, Faridabad were examined during the enquiry. As per Enquiry report the claimant was held guilty of the charges levelled against him. It was found that charge sheeted workman came in a drunken condition, abused and manhandled Mr. S.K.Katlaria and was held guilty of the charges levelled against him. This finding of the enquiry officer was accepted by the Disciplinary Authority Committee and the Appellate Authority accepted the findings and confirmed by the Appellate Authority. During enquiry Mr. Katlaria Manager deposed that Mr. Janak Raj (claimant) under the influence of Liquor entered his cabin, abused and assaulted him and gave a punch i.e. fist blow on his face causing injuries on his lips and teeth resulting in bleeding. Shri S.K.Malik (witness) saw him bleeding from his mouth during enquiry. Mr. Katlaria deposed that he was beaten by claimant Janak Raj Parashar. MW2 too deposed that he did not see Mr. Janak Raj Parashar claimant beating Mr. Katlaria nor any liquor was served. He too was told by Mr. Katlaria that he was beaten by the claimant. MW3 Y.L.Madan AGM investigated the matter which reportedly took place on 22-2-98 in the Currency Chest Faridabad.

3. Claim was contested by the management by filing written statement stating that the workman was working as a clerk since 29-4-1995 and while working at the Currency Chest Faridabad he was placed under suspension by the Disciplinary Authority in contemplation and initiation of disciplinary action vide orders dated 22-5-98 and thereafter he was charge-sheeted for gross misconduct vide charge sheet dated 9-7-98 wherein it was alleged that the (deceased) workman on 22-5-98 entered the Manager's cabin in a drunken state and abused and threatened M.S.Katlaria Manager without any provocation. He had also assaulted him in his cabin and punched him on his face causing injuries to his lips/teeth resulting in bleeding. The workman had committed a gross misconduct within the meaning of "Chapter 11, Regulation 3(k) and 3(m) of the Canara Banc Service Code. The workman did not submit any reply to the charge sheet and consequent thereupon the Disciplinary Authority appointed the Enquiry Officer to enquire into the charges levelled against the workman vide his proceedings dated 6-8-98. During enquiry five witnesses and 11 documents were produced on behalf of the management. After conclusion of the proceedings the Enquiry Officer vide his enquiry report dated 20-7-99 had found that the workman was guilty of the charges levelled

against him. Aggrieved by the said punishment the workman had preferred an appeal vide his representation dated 23-1-99 to the Appellate Authority of the Bank who gave a personal hearing to the claimant on 23-3-2000 at New Delhi. The Appellate Authority confirmed the punishment of compulsory retirement imposed upon the claimant and thus the appeal was rejected vide orders dated 11-5-2000. The said orders were conveyed to the workman vide proceedings dated 18-5-2000. It is stated that the enquiry proceedings were held in consonance with the principles of natural justice and the charges against the deceased were proved and thereafter the punishment of compulsory retirement was imposed upon the claimant. The L.R.s. of the deceased workman have no case for grant of monetary/consequential benefits.

4. Written statement was followed by rejoinder wherein the controverted facts of the written statement were refuted and those of claim statement were reiterated to be correct.

5. Smt. Chitra Parashar wife/L.R. of late Shri Janak Raj Parashar examined herself as WW 1 on behalf of the workman and management examined Shri R. Vishwanathan MW 1 on behalf of the management

6. I have heard Smt. Chitra Parashar Wife of the workman and Shri Rajat Arora on behalf of the management and perused the record meticulously.

7. Perusal of record shows that enquiry has been conducted by E.O. the workman initially attended the enquiry and later on proceeded ex parte during enquiry. 4-5 witnesses were examined. Mr. Katlaria Bank Manager deposed that he was given a fist blow on his face by Mr. Janak Raj which resulted in bleeding and that Mr. Janak Raj was drunk at the time when he gave beating in the office premises in his cabin without any provocation because he asked not to take whisky in the party of an officer who was transferred on account of which Mr. Katlaria entered in his cabin and gave him a fist blow. The act of giving beating by punching a senior officer in his face in drunken condition by the claimant certainly amounts to an act of misbehaviour on the part of the workman and thus he has committed an act of misbehaviour and has been aptly held guilty of misbehaviour by the Enquiry Officer and the Appellate Authority. It has been urged that the punishment of compulsory retirement is disproportionate and claimant deserved lesser punishment particularly when he is no more and since deceased. But I do not find any mitigating circumstance for giving any lesser punishment as giving beating to senior officer without any provocation is certainly very serious one and amounts to an act of indiscipline in official acts which is impermissible in discharge of official duty. The findings of the Enquiry Officer and Disciplinary Authority and punishment imposed needs no interference. In my opinion the action of the management of Canara Bank in compulsorily retiring the claimant from service for his act of misbehaviour is justified and legal. Award is passed accordingly. File be consigned to record room.

SANT SINGH BAL, Presiding Officer

Dated 16-10-07

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3534.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकारण/श्रम न्यायालय, चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 58/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।**

[सं. एल-12012/35/2005-आई. आर.(बी-II)]  
राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3534.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 58/2005) of Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Indian Bank, and their workmen, received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-12012/35/2005-IR (B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer  
ANNEXURE

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT  
CHENNAI**

Tuesday, the 25th Sept., 2007

Presiding Officer **K. JAYARAMAN**

**INDUSTRIAL DISPUTE No. 58/2005.**

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Indian Bank and their Workman.)

**BETWEEN**

Sri R. Thirumurthy I Party/Petitioner  
*Vs.*

The Assistant General Manager II Party/Management  
Indian Bank, Circle Office Trichy

**APPEARANCE:**

For the Petitioner M/s S. Ayyathurai and  
D. Bharathy, Advocates  
For the Management M/s King & Partridge,  
Advocates

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/35/2005-IR(B-II) dated 17-06-2005

referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule [amended by corrigendum dated 09-06-2006] mentioned in that order is :

"Whether the punishment of removal from service with superannuation benefits imposed on Shri R. Thirumurthy, sub-staff by the management of Indian Bank, Trichy vide order dated 12-07-2003 and 24-05-2004 is legal and justified? If not, what relief the Workman is entitled to?"

2. After the receipt of Industrial Dispute, it was taken on file as I.D. No. 58/2005 and notices were issued to both the parties and they have entered appearance through their advocates and filed their Claim Statement and Counter Statement respectively.

3. The allegations of the petitioner in the amended Claim Statement are briefly as follows :

The petitioner was working as sub-staff in Karur branch of the Respondent/Bank. While so, he was placed under suspension by the Disciplinary Authority by all order dated 15-07-2002 alleging that he fraudulently withdrew money from the account of a customer by name Mr. R. Marudhan by utilising the services of third parties. Show cause notice was issued to him and after that the Respondent/Management has framed charges on 05-10-2002 making the same allegations of fraudulent withdrawal of amount from the customer's account and ordered for enquiry. But, before this, the management had conducted preliminary enquiry by one Mr. R. Balakrishnan, Assistant Manager, Circle Office, Trichy. The petitioner even before him has denied the allegation and told that he had not done anything like that. But the Assistant Manager, Circle Office and Branch Manager one Mr. Rangarajan threatened the petitioner with police action for no fault of his and the petitioner had no other option but to admit the false allegations made against him. In these circumstances, he admitted the allegations and remitted the amount. Enquiry was conducted by the Senior Manager of the Respondent/Bank, but the enquiry was not conducted fairly and properly and in accordance with principles of natural justice. Though in the enquiry he asked time for cross-examination of witnesses, it was refused and thereby denied him the opportunity to defend himself effectively in the enquiry. Further, the Enquiry Officer did not allow the petitioner to let in any evidence saying that has already admitted the charge and no purpose would be served by letting in any evidence. Thus, the enquiry was conducted denying reasonable opportunity to the Petitioner to defend himself effectively in the enquiry. After the enquiry, the Disciplinary Authority after following the procedure has proposed the punishment of removal from service with superannuation benefits. The management without considering his explanation in a proper perspective imposed the punishment by an order dated 12-07-2003. The Appellate

Authority also by an order dated 25-04-2004 rejected the appeal without considering the same in a proper perspective. Therefore, the petitioner raised the dispute before labour authorities and on the failure of conciliation the matter was referred by the Govt. to this Tribunal for adjudication. The Disciplinary Authority and Appellate Authority failed to consider that he was not given a reasonable opportunity of defending himself effectively in the enquiry thereby enquiry was not conducted fairly and properly and in accordance with the principles of natural justice. The Disciplinary Authority and Appellate Authority failed to consider the fact that the petitioner was coerced to admit the false allegation made against him and the so called admission was not voluntary. Therefore, the findings of the Enquiry Officer are perverse and not based on any legal or acceptable evidence. The petitioner has nothing to do with the fraudulent withdrawal of money from the account of the customer Mr. Marudhan on the two alleged occasions and they have been committed by outsiders. The petitioner is innocent and ignorant of charges and he has not committed the misconduct alleged against him. The punishment imposed on him by the management is highly disproportionate to the gravity of the charges. Hence, for all these reasons, he prays to set aside the punishment of removal from service and to direct the Respondent/Management to reinstate the petitioner into service with continuity of service and other attendant benefits.

4. As against this, the Respondent in its Counter Statement contended that it is true that show cause notice dated 02-08-2002 was issued to the petitioner for the reported misappropriation of bank's money and he was given ten days time for filing his reply. But, the petitioner has not submitted any reply nor he sought for extension of time. Therefore, charge sheet was issued on 05-10-2002 for the misconduct alleged against him. The petitioner appointed, one Mr. Syed Hussamudeen of Indian Bank Staff Union as his defence representative, who is a veteran trade union leader having Master of Law degree. In the domestic enquiry six witnesses were examined and 15 documents were marked on the side of Respondent/Management. witnesses were cross examined by the defence representative. On behalf of the petitioner two defence exhibits were marked. The defence representative and delinquent employee consciously took the decision of not producing any witness on their side. After that an opportunity was given to the petitioner to submit his submission. Thereafter the Enquiry Officer prepared the enquiry report dated 07-03-2003 elaborately analysing oral and documentary evidence and held that all the charges against the delinquent employee were proved beyond doubt. Thus the enquiry was conducted in accordance with principles of natural justice and full opportunity was given to the delinquent employee to defend the charges. It is false to allege that the services of the petitioner are

unblemished. The past service records, of the petitioner was not satisfactory. No doubt, the Disciplinary Authority placed him under suspension by his order dated 15-07-2002, but only in connection with the fraudulent withdrawal of Rs. 20,000/- from the account Mr. Maudhan by utilising the services of third party. When the fraudulent withdrawal came to light after marshalling the details on the alleged involvement of the petitioner, then only the show cause notice was issued to him. Further, if the petitioner's stand that he was coerced and threatened with police action by the Investigation Officer is correct, he would have reported the matter either orally or in writing in the language known to him to the higher authorities immediately. But, he has not done anything. Therefore, the stand now taken by him is an afterthought. The petitioner himself came forward to give confession and the same was obtained in the presence of the II Party/Management. The petitioner has not stated as to how the Respondent/Bank failed to adhere to the principles of natural justice or the manner of conducting the enquiry. The defence representative defended the petitioner in the enquiry in his capacity as President of the Union, he being a veteran trade union leader, the allegation of the petitioner that the defence representative also succumbed to the pressure of the management and failed to produce any evidence on his side is nothing but imaginary. The Disciplinary Authority and Appellate Authority had given reasons for their conclusion and therefore, it is false to allege that he has not given any reasonable opportunity to defend himself. The findings of the Enquiry Officer is on the basis of legal and acceptable evidence. Since the Respondent being financial institution, the frauds committed by its employee cannot be taken lightly, hence the misconduct committed by the petitioner is grave in nature and called for deterrent punishment. Hence, for all these reasons, the Respondent prays that the claim may be dismissed with costs.

#### Points for determination:

- (1) Whether the punishment of removal from service, imposed on the petitioner by the Respondent Management by its order 4-05-2004 is legal and justified?

(2) "To what relief the petitioner is entitled to?"

5. In this case, both sides have not adduced any oral evidence before this Tribunal. The petitioner's documents have been marked as W2 to W5. The learned counsel for the petitioner argued that the findings of the Enquiry Officer are perverse since they are not based on any acceptable legal evidence. He has further argued that the Management witnesses MW2 & MW3 have deposed about the 3rd party who came to the bank, have taken the money, the Enquiry Officer has not relied on the evidence given by these persons and he has not given any reason to reject the arguments of the defence representative, has given a

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour vide its Order No. L-12012/107/2006 IR(B-II) dated 28-05-2007 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is :

"Whether the action of the management of Indian Overseas Bank in dismissing the services of Sri R. Mohan is legal and justified? If not, to what relief is the workman entitled to?

2. After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 26/2007 and issued notices to both sides. Even after several notices, the petitioner has not appeared before this Tribunal. On the other hand, the Respondent appeared through their advocate and filed their Memo of Objection. The petitioner called and set ex-parte on 27-09-2007.

3. The allegation in the objection filed by the Respondent are briefly as follows:

Though the petitioner has raised the dispute, he has not appeared before this Tribunal and this clearly establishes that he is not interested in contesting the I.D. Hence the Respondent prays to dismiss the I.D. with costs.

**Point for determination is:**

1. Whether the action of the management of Indian Overseas Bank in dismissing the services of Sri R. Mohan is legal and justified?
2. If not, to what relief is the workman entitled to?"

**Point No.1 & 2**

4. As I have already pointed out, the petitioner though has raised the dispute before the labour authorities. After the dispute was referred to this Tribunal, he has not appeared before this Court to establish his case whether the Respondent Management has illegally terminated his services without any reason or rhymes. Since the petitioner has not appeared before this Tribunal to establish his case, this Tribunal is not in a position to say whether the action taken by the Respondent Bank in dismissing the petitioner from service is legal or justified.

5. As against this, the Respondent contended that since the petitioner has no interest in the case and remained ex parte the dispute is to be dismissed with their costs. Therefore, I find since the petitioner has not established before this Tribunal that the action taken by the Respondent Bank is illegal and unjustified, I find the petitioner is not entitled to any relief.

6. Thus, the reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A. transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 29th October, 2007)

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

**Witnesses Examined:**

For the I Party/Petitioner	None
----------------------------	------

For the II Party/Management	None
-----------------------------	------

**Documents Marked :**

Ex. No.	Date	Description
---------	------	-------------

Nil

From the Management side:

Ex.No.	Date	Description
--------	------	-------------

Nil

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3536.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार इंडियन बैंक के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/ श्रम न्यायालय, चेन्नई के पंचाट (संदर्भ संख्या 33/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-12011/24/2007-आई. आर.(बी-II)]

राजिन्द्र कुमार, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3536.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 33/2007) of Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Chennai as shown in the Annexure in the industrial dispute between the management of Indian Bank, and their workman, received by the Central Government on 23-11-2007:

[No. L-12011/24/2007-IR (B-II)]

RAJINDER KUMAR, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT**

**CHENNAI**

Wednesday, the 29th August, 2007

PRESENT : K. JAYARAMAN

Presiding Officer

**INDUSTRIAL DISPUTE No. 33/2007**

(In the matter of the dispute for adjudication under clause (d) of sub-section (1) and sub-section 2(A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947(14 of 1947), between the Management of Indian Bank and their Workmen)

**BETWEEN**

The General Secretary  
Indian Bank Employees  
Union, Chennai

I Party/Petitioner Union

*Vs*

The Dy. General Manager      II Party/Respondent  
 Indian Bank Kanchipuram

**APPEARANCE**

For the Petitioner	:	Sri E. Arunachalam Authorised Representative
For the Management	:	Sri P. Sankar Authorised Representative

**AWARD**

The Central Government, Ministry of Labour vide its Order No. L-12011/24/2007/IR(B-II) dated 04.07.2007 referred the following Industrial Dispute to this Tribunal for adjudication.

The schedule mentioned in that order is :

"Whether the action of the management in withholding of increments due to Sri G. Elango is justified? If not, to what relief is the workman entitled?"

2. After the receipt of Industrial Dispute, this Tribunal has numbered it as ID 33/2007 and issued notices to both sides. Both sides have entered through their representatives. The petitioner's representative filed a memo stating since the Respondent/Management has already sanctioned the annual increment due to Sri Elango, Clerk/Shroff, the grievance of the employee is already redressed and therefore the dispute is not now in existence and therefore the issue may be treated as amicably resolved.

3. The representative of the second party management filed a memo stating that in view of the memo filed by the petitioner union, this dispute may be closed as withdrawn and request this Tribunal to pass an order to that effect. In these circumstances, the point of determination is :

(i) To what relief the concerned employee is entitled to:

4. Since the petitioner union has filed a memo stating that the increments has been given by the Respondent/Management after the petitioner union raised the dispute before the labour authorities and further stated that the issue in this dispute has already been settled amicably and therefore there is no necessity to proceed with the enquiry. Since the petitioner has filed this memo that the dispute has been settled, I find there is no use in proceeding this dispute.

5. In view of the my foregoing findings, I find this dispute as settled and therefore this Tribunal has no need to pass any award.

6. Thus, the reference is answered accordingly.

(Dictated to the P.A. transcribed and typed by him, corrected and pronounced by me in the open court on this day the 29th August, 2007)

K. JAYARAMAN, Presiding Officer

**Witnesses Examined:**

For the I Party/Petitioner	None
For the II Party/Management	None

**Documents Marked :**

From the Petitioner's side

Ex.No.	Date	Description
		Nil

From the Management side:

Ex.No.	Date	Description
		Nil

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

का. आ. 3537.—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसार में, केन्द्रीय सरकार एयर इंडियन लिमिटेड के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण /श्रम न्यायालय, मुम्बई-2 के पंचाट (संदर्भ संख्या 86/2005) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/14/2005-आई आर(सी-1)]  
 स्नेहलता जावास, डेर्स्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

S.O. 3537.—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 86/2005) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court, Mumbai-2 as shown in the Annexure in the industrial dispute between the the employers in relation to the management of Air India Limited, and their workman, which was received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-11012/14/2005-IR (C-I)]

SNEHLATA JAWAS, Desk Officer

**ANNEXURE-I****BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT  
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. 2, MUMBAI.**

**PRESENT A. A. LAD, Presiding Officer**

**REFERENCE NO. CGIT-2/86 OF 2005**

**EMPLOYERS IN RELATION TO THE  
MANAGEMENT OF M/S. AIR INDIA LTD.**

The Chairman-cum-Managing Director

M/s. Air India Ltd.  
Old Airport  
Santacruz (E)  
Mumbai-400 029.

AND

THEIR WORKMEN

The President,  
Air India Employees Guild Old Airport,  
Santacruz (E)  
Mumbai-400 029.

#### APPEARANCES

For the employer M/s. M. V. Kini & Co.  
Advocates

For the workmen No appearance

**Corrigendum to award dated 29th August, 2007**

Ministry's Order No. L-30012/85/2001-IR(M), dated 23rd January, 2001 appearing on page 2, 3rd line of the 1st paragraph may be read as Order No. L-11012/14/2005-IR (C-I), dated 2-6-2005.

Date: 12-10-2007

A. A. LAD, Presiding Officer

#### ANNEXURE-II

#### BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL NO. II AT MUMBAI

#### PRESENT

**A.A. LAD, PRESIDING OFFICER**

**REFERENCE NO. CGII-2/86 OF 2005**

**EMPLOYERS IN RELATION TO THE MANAGEMENT  
OF M/S. AIR INDIA LIMITED**

The Chairman-cum-Managing Director,  
M/s. Air India Limited,  
Old Airport, Santacruz (East),  
Mumbai 400 029. ....First Party.

AND

Their workman  
The President,  
Air India Employees Guild,  
Old Airport, Santacruz (East),  
Mumbai-400 029. ....Second Party

#### APPEARANCES

For the employer M/s. M. V. Kini & Co.,  
Advocates

For the workman : No appearance

Date of Psssing of Award I : 29th August, 2007

#### AWARD

The reference is sent to this Tribunal by the Under Secretary of Central Government, The Government of India, Ministry of Labour by its Order No. L-30012/85/2001-IR(M) dated 23rd January, 2001 in exercise of the powers conferred by Clause (d) of sub-section (1) and sub-section (2A) of Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 to decide:

"Whether the demand of the Air India Employees Guild from the management of Air India that Sh. S.U. Chandan Shive be appointed as Trainee Technician with all consequential benefits w.e.f. 1984 justified? If so, to what relief is the workmen entitled?

(2) After receipt of the Reference it was fixed for filing Statement of Claim by 2nd Party. However, Claim Statement is not filed by 2nd Party though number of dates were given. Hence, the order:

#### ORDER

Reference is disposed off for want of prosecution.

Mumbai,

29th August, 2007.

A. A. LAD, Presiding Officer

नई दिल्ली, 26 नवम्बर, 2007

**का. आ. 3538:**—औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 17 के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार रशियन एयर लाइंस के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण/श्रम न्यायालय, नई दिल्ली-2 के पंचाट (संदर्भ संख्या 25/2007) को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 23-11-2007 को प्राप्त हुआ था।

[सं. एल-11012/54/2007-आई आर(सी-1)]

स्नेहलता जावास, डेस्क अधिकारी

New Delhi, the 26th November, 2007

**S.O. 3538.**—In pursuance of Section 17 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby publishes the Award (Ref. No. 25/2007) of the Cent. Govt. Indus. Tribunal-cum-Labour Court New Delhi-II now as shown in the Annexure in the industrial dispute between the employers in relation to the Russian Air Lines, and their workmen, which was received by the Central Government on 23-11-2007.

[No. L-11012/54/2007-IR (C-I)]

SNEHLATA JAWAS, Desk Officer

**ANNEXURE**

**BEFORE THE PRESIDING OFFICER: CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL-CUM-LABOUR COURT - II, RAJENDRA BHAWAN, GROUND FLOOR, RAJENDRA PLACE, NEW DELHI**

**PRESIDING OFFICER: R.N.RAJID. No. 25/2007**

In the matter of:

Shri Hirminder Singh,  
S/o. Shri Saran Singh,  
R/o. B-57, IAAI Colony,  
Mahipalpur, Palam Colony,  
New Delhi - 110037.

**VERSUS**

The General Manager,  
Aeroflot, Russian Airlines,  
Ground Floor, Tolstoy Marg,  
15 - 17 , Tolstoy Marg,  
New Delhi - 110001.

**AWARD**

The Ministry of Labour by its letter No. L-11012/54/2007-IR(CM-I) Central Government Dt. 02-07-2007 has referred the following point for adjudication.

The point runs as hereunder :

Whether the action of the management of Aeroflot, Russian International Airlines, New Delhi in dismissing the services of Shri Haminder Singh w.e.f. 30-04-2006 is justified and legal? If not, to what relief is the concerned workman entitled?"

It transpires from perusal of the order sheet that the reference has been received on 17-07-2007. Four dates have been given thereafter. The workman was not present. No claim statement has been filed.

No dispute award is given.

Date: 20-11-2007.

R. N. RAI, Presiding Officer